दिसम्बर, 2023, वर्ष : 44 अंक : 12

www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

तिब्बत देश

तिब्बत पोटाला महल ।

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

दिसम्बर, 2023, वर्ष : 44 अंक : 12

तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम मे परम पावन दलाई लामा।

प्रधान संपादक
जमयंग दोरजी, थुप्तेन रिन्ज़ीन

सलाहकार संपादक
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

प्रबंध संपादक
तेनजिन जोरदेन

वितरण प्रबंधक
छोन्यी छरिंग, ताशी देकि

संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

समाचार -

- प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन 1
- सिक्किम के मुख्यमंत्री ने परम पावन दलाई लामा का स्वागत किया 2
- परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की ३४वीं वर्षगांठ पर कशाग का वक्तव्य 3
- सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने पेरिस में तिब्बत समाधान अधिनियम को एचएफएसी की मंजूरी पर चर्चा की 4
- ताशी ल्हुनपो मठ ने भारत सरकार से तिब्बत के ११वें पंचेन लामा को रिहा करने के लिए चीन पर दबाव डालने की अपील की 5
- तिब्बतियों को माओ का १३०वां जन्मदिन मनाने के लिए मजबूर किया गया चीनी अधिकारियों ने माओ द्वारा तिब्बत पर १९५० के चीनी आक्रमण से पहले के तिब्बतियों को 'गरीब-वंचित' दिखाते हुए प्रचार -प्रसार किया है। 6
- सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने २७वें हिमालय महोत्सव में भारत-तिब्बत संबंधों की स्थिरता के लिए आशा व्यक्त की 7
- 'स्वीडिश पार्लियामेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर तिब्बत' ने तिब्बत पर प्रस्ताव रखा 8
- बीजिंग में आयोजित २४वें ईयू-चीन शिखर सम्मेलन के दौरान तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठा 9
- डिप्टी स्पीकर के नेतृत्व में तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में तिब्बत के पक्ष में अभियान शुरू की 10

समाचार -

- यूरोपीय संघ की संसद में चीन द्वारा संचालित औपनिवेशिक शैली के आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों को जबरन भर्ती करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित 11
- इंडिया सोशल फोरम में चला तिब्बत जागरुकता अभियान 12
- परम पावन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की ३४वीं वर्षगांठ पर आईटीएफएस का तीसरा महाराष्ट्र सम्मेलन आयोजित 13
- भारत में तिब्बत समर्थक समूह के क्षेत्रीय संयोजक ने गुजरात में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संगोष्ठी आयोजित की 14
- तिब्बत को लेकर चीन का नया दुष्प्रचार भारत के लिए चिंता की बात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रशासन ने तिब्बत के विकास को प्रदर्शित करने वाले अपने हालिया 'श्वेत-पत्र' में तिब्बत को 'ज़िज़ांग' नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया है। 15

मुद्रक एवं प्रकाशक
जमयांग दोरजी द्वारा
नोरबू ग्राफ़िक्स , 1/6, बेसमेंट
विक्रम विहार , लाजपत नगर
नई दिल्ली - 110024

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
coordinator@indiatibet.net

◆ दलाई लामा को नोबल पुरस्कार की वर्षगाँठ पर निर्णायक संघर्ष का संकल्प

वयोवृद्ध बौद्ध धर्मगुरु परमपावन दलाईलामा के प्रति लोगों की श्रद्धा लगातार बढ़ती जा रही है। इसका ठोस प्रमाण है उनकी सिक्किम यात्रा। इसी दिसबंर, 2023 में उन्हें सिक्किम सरकार ने सादर आमन्त्रित किया था। इसके लिये और इससे भी बढ़कर उनके दर्षन हेतु मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग तीन-चार बार हिमाचल प्रदेष के कांगड़ा जिले में धर्मषाला स्थित उनके आवास पहुँचे। उनके ऊपर सिक्किम की जनता का दबाव बढ़ता जा रहा था। दलाईलामा सात-आठ साल से सिक्किम गये नहीं थे। सिक्किम में लाखों लोगों ने दलाईलामा के अभिनंदन तथा प्रवचन में शामिल हो उनके आषीर्वाद प्राप्त किये। इन कार्यक्रमों में राज्यपाल महोदय, मंत्रीगण, अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा पत्रकार एवं विद्वान् भी उपस्थित रहे। विभिन्न रिलिजन (मत, पंथ, मज़हब, संप्रदाय) के अनुयायी भी दलाईलामा के प्रेरणापूर्ण प्रवचनों से लाभान्वित हुए। सिक्किम सरकार द्वारा दलाईलामा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए भव्य भोज का आयोजन किया गया। स्वागत एवं सम्मान करने के नाम पर सिक्किमवासी दलाईलामा के प्रेरक योगदान के लिये उनके प्रति भावपूर्ण आभार प्रकट कर रहे थे।

सिक्किम जैसा ही वातावरण पष्चिम बंगाल के सालूगाड़ा में था। यहाँ भी दलाईलामा के प्रवचन में असंख्य लोग पहुँचे। सभी उनके दीर्घजीवन हेतु भगवान् बुद्ध से प्रार्थना कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि दलाईलामा अपनी आयु के 89वें वर्ष में हैं। इस उम्र में भी वे पूर्णतः स्वस्थ तथा सक्रिय हैं। वे अपने आध्यात्मिक दायित्व कुषलतापूर्वक निभा रहे हैं। अपनी लंबी उम्र के बावजूद वे यहाँ से पहुँचे बोधगया।

भगवान् बुद्ध को ज्ञानप्राप्ति बोधगया में हुई थी। यहाँ अनेक देषों के बौद्ध मतावलंबियों ने भव्य-दिव्य मंदिर बनवाये हैं। दलाईलामा के आध्यात्मिक अनुष्ठान, प्रवचन एवं उपदेष में भारी भीड़ उमड़ती है। इस वर्ष भी यहाँ यही देखने को मिला। लोग उनके दर्षन कर स्वयं को धन्य कर रहे थे। दलाईलामा अपने प्रवचनों में मानवीय मूल्यों की मजबूती पर जोर देते हैं। उनके अनुसार ये मूल्य प्रत्येक अर्थात् सभी के लिये समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, वह ईष्वर या आत्मा में विष्वासी हो या अविष्वासी हो- उसे भी जीवन में मूल्य अपनाने होंगे। बौद्ध दर्षन की प्राचीन नालंदा परंपरानुसार ये जीवन मूल्य हैं-शांति, अहिंसा, करुणा, मैत्री, सेवा-सद्भाव तथा परोपकार।

दलाईलामा की मानवीय मूल्यों के प्रति आचार-विचार-व्यवहार में निष्ठा का एक ठोस प्रमाण है नोबल शांति पुरस्कार। उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की 34 वीं वर्षगाँठ इसी 2023 में है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर को उन्हें यह सम्मानपूर्ण पुरस्कार दिया गया था। प्रतिवर्ष इसी उपलक्ष्य में तिब्बती एवं तिब्बत समर्थक विष्वभर में विभिन्न विषेष आयोजन करते हैं। इनमें तिब्बत में जारी चीनी अत्याचार से विष्व समुदाय को अवगत कराया जाता है। शांतिपूर्ण प्रदर्षन, रैली, सभा तथा षिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिये प्रतियोगिताओं के संयोजन से तिब्बती संघर्ष को नई ऊर्जा मिलती है। इस वर्ष भी ऐसा विष्वस्तर पर हुआ। तिब्बत में

मानवाधिकारों के हनन के लिये साम्राज्यवादी चीन की कटु आलोचना की गई। सभी सहभागी संगठन एवं विचारक तिब्बती संघर्ष को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये एकजुट दिखाई दिये।

मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में तिब्बती आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं अहिंसक बनाये रखने पर जोर दिया गया। दलाईलामा का यही निर्देष है। वे कहते हैं कि तिब्बती संघर्ष हमारा पवित्र उद्देष्य है इसलिये इसकी सफलता के लिये हमें शांति-अहिंसा जैसे पवित्र साधनों का उपयोग करना है। वे इस विषय में गांधी-दर्षन से प्रभावित हैं। वह भी पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिये पवित्र साधन अपनाने की सलाह देता है। इन कार्यक्रमों में सभी राष्ट्रीय-क्षेत्रीय-अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से अपील की गई कि वे तिब्बत की अत्यन्त दयनीय स्थिति को समाप्त करने हेतु चीन सरकार पर दबाव बढ़ायें। चीन सरकार हांगकांग, ताइवान, इस्ट तुर्किस्तान तथा मंगोलिया में भी व्यापक पैमाने पर मानवाधिकारों का दमन कर रही है। चीन सरकार की मानवाधिकार विरोधी नीति का विरोध विष्व की सम्पूर्ण लोकतांत्रिक शक्तियों का महत्वपूर्ण कर्तव्य है।

चीन सरकार अपने पड़ोसी देषों का साजिषपूर्वक चीनीकरण कर रही है। सभी के भूभाग का अतिक्रमण कर रही है। इनके पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है तथा इनकी प्रकृति एवं सम्पत्ति को बर्बाद कर रही है। इनके प्रषासन पर उसका प्रभावी नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। भारत में भी वह अलगाववाद-आतंकवाद तथा तस्करी को बढ़ा रही है। तिब्बत पर अवैध नियंत्रण कर चुके चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुष लगाने के लिये संगठित प्रयास करना होगा।

तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमण्डल ने भी अपने वार्षिक तिब्बती जागरुकता अभियान में “साजिषपूर्ण चीनीकरण नीति” को सप्रमाण उजागर किया है। निर्वासित तिब्बत सरकार, जो कि वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित तिब्बत सरकार है, के कार्यालय विभिन्न देषों में कार्यरत हैं। दिसम्बर में अपने भ्रमण के दौरान तिब्बती राजदूतों (प्रतिनिधियों) ने अपनी नियुक्ति वाले देषों में विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों, मीडियाकर्मियों, कलाकारों, साहित्यकारों तथा जनमतनिर्माता विचारकों के साथ सार्थक संवाद किया। उन्होंने आह्वान किया कि पूर्ण स्वतंत्रता की जगह तिब्बत को “वास्तविक स्वायत्तता” दी जाये। यही मध्यममार्ग नीति है, जो कि चीनी संविधान और राष्ट्रीयता संबंधी कानून के भी अनुकूल है। चीन के पास प्रतिरक्षा एवं विदेष विभाग हो। धर्म, संस्कृति भाषादि विषय तिब्बतियों को मिलें। इस समाधान से चीन की संप्रभुता सुरक्षित रहेगी और तिब्बतियों को स्वषासन का अधिकार मिल जायेगा।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

◆ प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन

dalailama.com, २० दिसंबर, २०२३

बोधगया, बिहार, भारत। परम पावन दलाई लामा ने २० दिसंबर, २०२३ की सुबह गैंडेन पेलग्येलिंग मठ से बोधगया के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तक छोटी दूरी तय की, जहां उन्हें पहले अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम (आईएसएफ) के उद्घाटन सत्र में भाग लेना था। आयोजन समिति के सदस्यों ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। अंदर जाने से पहले, उन्होंने अपने आगमन के जश्न में लॉन में नृत्य कर रहे अरुणाचल प्रदेश के मोनपाओं के एक समूह के नृत्य का आनंद लिया।

एक बार जब परम पावन ने गैंडेन त्रि रिनपोचे और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के बीच मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया तो संचालक वेन महायानो औन ने बुद्ध, धर्म और संघ को श्रद्धांजलि अर्पित की, परम पावन को प्रणाम किया और इस सबसे पवित्र स्थान पर सभी बौद्ध परंपराओं के प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। उन्होंने घोषणा की कि फोरम का उद्देश्य २१वीं सदी में बौद्ध धर्म की भूमिका पर एक संवाद आयोजित करना और बौद्ध परंपराओं के बीच समझ और सहयोग बनाने के तरीकों पर चर्चा करना है। उन्होंने घोषणा की कि तीन दिनों तक चर्चा होगी, उसके बाद चौथे दिन महाबोधि मंदिर के आसपास विश्व में शांति के लिए प्रार्थना की जाएगी। सिलिंग टोंगखोर रिनपोचे ने तिब्बती भाषा में लिखे गए इस परिचय का अंग्रेजी में अनुवाद किया।

आरंभ में थेरवादी भिक्षुओं के एक समूह ने पाली में 'कारनिया मेट्टा सुट्टा (प्रेम-कृपा पर बुद्ध के वचन)' का पाठ किया। इसके बाद वाराणसी से संस्कृत विश्वविद्यालय के भिक्षुओं का एक समूह आया, जिन्होंने संस्कृत में मंगल सूत्र- शुभता का सूत्र- का जाप किया।

मॉडरेटर ने परम पावन और अन्य नेताओं से ज्ञानदीप जलाने और कार्यवाही शुरू करने के लिए सामने का बटन दबाने का अनुरोध किया। परम पावन ने जैसे ही बदन दबाया, चमकता हुआ बहुरंगी बिजली का लैंप उनके सामने दमक उठा और इसकी प्रतिछवि पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर देदीप्यमान हो उठा।

अंतरराष्ट्रीय संघ मंच की सचिव सुश्री वी नी एनजी ने आईएसएफ की इस पहली बैठक में परम पावन दलाई लामा, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने दोहराया कि इसका उद्देश्य बौद्ध पाली और संस्कृत परंपराओं के बीच सहयोग स्थापित करना और २१वीं सदी में बौद्ध होने के मायने पर चर्चा करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान देगा।

अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) के महानिदेशक अभिजीत हलदर ने कहा कि इतनी सम्मानित सभा के सामने बोलना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस सम्मेलन के संदेश का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मानवता ने हाल ही में बार-बार बाढ़, सूखे और भूकंप की घटनाओं को देखा है। महासागर बढ़ रहे हैं, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी कम हो रही है। उन्होंने कहा, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया है कि प्रकृति हमसे इतनी नाराज हो गई है। यह हमें अपने आप से यह पूछने के लिए मजबूर करता है कि हमसे कहां गलती हुई है और हमें आगे क्या करना चाहिए।

उन्होंने १९९२ में रियो दि जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में परम पावन द्वारा कही गई बात को उद्धृत किया :

'मेरा मानना है कि हमारे समय की चुनौती का सामना करने के लिए मनुष्य को अपने आप में वैश्विक जिम्मेदारी निभाने की महती भावना विकसित करनी होगी। हममें से प्रत्येक को न केवल अपने लिए, परिवार या राष्ट्र के लिए, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हित में काम करना सीखना चाहिए। वैश्विक जिम्मेदारी मानव अस्तित्व के लिए वास्तविक मूल बात है। यह जिम्मेदारी विकसित होने से मनुष्य में विश्व शांति, प्राकृतिक संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग और भावी पीढ़ियों की चिंता की समझ आती है और यही चिंता पर्यावरण की उचित देखभाल का सबसे अच्छा आधार बनती है।

हलदर ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में छिड़े युद्ध के माहौल में धर्म का मुख्य ध्यान करुणा और ज्ञान विकसित करने पर होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बौद्ध धर्म वैश्विक संस्कृति का हिस्सा है। यह हमें यह सिखाता है कि समृद्धि और करुणा से युक्त होकर कैसे शांति में रहा जा सकता है। हमें अपना ध्यान मनुष्य को अधिक दयालु और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में केंद्रित करने की आवश्यकता है। बुद्ध के उपदेश हमें दिखाते हैं कि दुखों को दूर करने के उद्देश्य से शांति और सद्भाव में कैसे रहना है। यही वह उपदेश है, जिन्हें सम्राट अशोक ने पूरे एशिया में फैलाने का आदेश दिया था।

हलदर ने परम पावन द्वारा शांतिदेव के 'बोधिसत्वाचार्यवतार' से अत्यधिक पसंद किए गए एक श्लोक का हवाला देते हुए अपनी बात समाप्त की-

जब तक अंतरिक्ष कायम है,
और जब तक भव्य प्राणी रहेंगे,
दुनिया के दुख को दूर करने में मदद के लिए.
तब तक मैं भी रहूंगा।

इसके बाद मॉडरेटर भिक्षु महायानो औन ने परम पावन से सम्मेलन का उद्घाटन भाषण देने के लिए कहा। इससे पहले उन्होंने परम पावन को उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया।

परम पावन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, 'मैं अपने मन, वचन और कर्म से बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम उस पवित्र स्थान पर एकत्रित हैं, जहां शाक्यमुनि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यद्यपि हम घोर

कलियुग में रह रहे हैं, फिर भी उन्होंने जो धर्म सिखाया वह अभी भी उज्ज्वल है।'

'बुद्ध न कभी पाप कर्मों को पानी से नहीं धोते, न ही वे अपने हाथों से प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं और न ही वे अपने विचारों को दूसरों पर थोपते हैं। बल्कि, सत्य को उजागर करके ही वे प्राणियों को मुक्त होने में मदद करते हैं।'

"हम अपनी विनाशकारी भावनाओं के कारण कष्ट उठाते हैं। अज्ञानता के कारण हम नकारात्मक कर्म अर्जित करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने हमें सिखाया कि गलत मत करो, अपने अंदर सद्गुण विकसित करो।' इसलिए हमें सुहृद बनने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचने की जरूरत है। हमें दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने की बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए और उनको लाभ पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से हमें मानसिक शांति मिलेगी। बदले में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

'क्रोध या मोह के वशीभूत होकर कार्य करना गलत है। धर्म का सार है जो हमें सीखना है- उसके लिए अध्ययन करना, जो सीखा है उसका मनन करना और जो समझा है उसे अपने जीवन में उतारना। यदि आप परोपकारी रवैया अपनाते हैं, बोधिचित्त का विकास करते हैं तो आप अपने और दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। 'मैं बोधिचित्त उत्पन्न कर सकता हूं'- का ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्ति के अवसर पर सभी भव्य प्राणियों को अपने अतिथि के रूप में बुलाएं। बोधिचित्त के लिए साधना करना शक्तिशाली अभ्यास है। इसके साथ ही हम छह सिद्धियों और शिष्यों को एकत्रित करने के चार तरीकों पर काम कर सकते हैं। पूरा ध्यान अन्य भव्य प्राणियों की सेवा पर होना चाहिए है। ऐसा करने लगेंगे तो दुनिया बेहतर मित्रतापूर्ण और अधिक शांतिपूर्ण जगह बन जाएगी।'

परम पावन ने सातवीं शताब्दी के तिब्बती धार्मिक राजा सोंगत्सेन गम्पो के समय की याद दिलाई। राजा सोंगत्सेन गम्पो ने देवनागिरी वर्णमाला पर आधारित एक तिब्बती लिपि तैयार की। नतीजतन, जब अगली शताब्दी में शांतरक्षित तिब्बत आए तो उन्होंने तिब्बतियों को पाली और संस्कृत भाषाओं पर भरोसा करने के बजाय बौद्ध साहित्य का तिब्बती में अनुवाद करने की सलाह दी। इसी अनुवाद के आधार पर धर्मग्रंथों और ग्रंथों के कांग्यूर और तेंग्यूर संग्रह तैयार हुए हैं, जिन पर हमें गर्व हो सकता है। इन संग्रहों को संरक्षित करना न केवल हमारे लिए अच्छा है बल्कि बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकता है।

परम पावन ने टिप्पणी की कि लोग भौतिकवाद से थक रहे हैं। इन परिस्थितियों में यदि हम सौहार्दता विकसित कर सकें तो हम न केवल शारीरिक रूप से सहज महसूस करेंगे बल्कि हमारा मन भी आनंद से भर जाएगा। इससे भी अधिक यह अगले जीवन में और अधिक सौहार्दपूर्ण होने में सहायक बनेगा।

परम पावन ने बताया, 'बोधिचित्त की साधना अनमोल साधना है। मैंने पाया है कि यह मेरे लिए बहुत मददगार रहा है। इसलिए मैं आप सभी से भी इसे ध्यान में रखने के लिए कहता हूँ। अन्य प्राणियों की सहायता करें, उनके लिए खुद बुद्ध बनें। अपने मन की शांति विकसित करके हम विश्व में शांति के लिए व्यावहारिक योगदान दे सकेंगे।'

'मैंने बोधिचित्त और शून्यता को समझने वाले ज्ञान के लिए की गई साधना के लाभों को देखा है और मैं अपने अनुभव से उनके व्यावहारिक अवदान को प्रमाणित कर सकता हूं। मैंने एकल-केंद्रित एकाग्रता विकसित नहीं की है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। इस तरह से बोधिचित्त आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास लाता है। यह हमें सभी संवेदनशील प्राणियों के लिए काम करने का साहस देता है।'

परम पावन ने टिप्पणी की कि 'हृदय सूत्र' का मंत्र बुद्धत्व प्राप्ति के लिए चरण-दर-चरण आगे बढ़ने का संकेत देता है। जब अवलोकितेश्वर 'तद्यता गते गते परगते पारसमगते बोधि स्वाहा (आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, पूरी तरह से आगे बढ़ें, आत्मज्ञान में स्थापित हों)' का पाठ करते हैं तो वह शिष्यों को पांच मार्गों से आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। परम पावन ने यह भी उल्लेख किया कि नागार्जुन की 'मध्यम मार्ग की मौलिक बुद्धि', शांतिदेव की 'बोधिसत्व के मार्ग में प्रवेश' और चंद्रकीर्ति की 'मध्यम मार्ग में प्रवेश' जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत उपयोगी हो सकता है।

परम पावन ने कहा, 'दूसरों के साथ अनुभव साझा करने के लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए। दो सिद्धांत- बोधिचित्त और शून्यता- को समझने वाली बुद्धि मेरी साधना का मूल है। मैं हर दिन सुबह उठते ही उनका आह्वान करता हूं। इस प्रकार मैं पुण्य इकट्ठा करता हूं और मानसिक मलिनता को शुद्ध करता हूं। जब तक अंतरिक्ष मौजूद है मैं लगातार दूसरों की सेवा करने की इच्छा प्रकट करता हूं। दूसरों की भलाई करना ही सार्थक जीवन जीने का तरीका है।

यदि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को अनुशासित करने की आवश्यकता है। मैं अपने धर्म मित्रों से इसे हृदयंगम करने के लिए कहता हूं। मेरा जन्म सुदूर उत्तर-पूर्वी तिब्बत में हुआ था और बचपन में पढ़ाई के लिए मुझे ल्हासा लाया गया था। अब मैं महसूस कर सकता हूं कि इन प्रथाओं का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि मैं इन्हें आपके साथ साझा करने में सक्षम हूं। मैं आपसे बोधिचित्त और शून्यवाद को समझने के लिए चिंतन करने का आग्रह करता हूं।

'पाली और संस्कृत दोनों परंपराओं का सार परोपकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात बोधिचित्त में स्थिर होना है।'

सभा को कई बौद्ध परंपराओं के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। ताइवान के ब्लिस एंड विजडम मठवासी समुदाय के मठाधीश वेन रु-जिंग ने मंच को अपनी शुभकामनाएं दीं। बोधगया में थाईलैंड के राजा के प्रतिनिधि के तौर पर रॉयल थाई मठ के मुख्य मठाधीश फ्रा धम्बोधिवोंग ने थाईलैंड के थाई संघराजा और शाही परिवार की ओर से परम पावन को बधाई दी और त्रिरत्न से प्रार्थना की कि मंच और इसकी कार्यवाही को आशीर्वाद दें।

भूटान के जेई खेंपो कार्यालय के अनुसंधान और अनुवाद प्रमुख भिक्षु खेंपो सोनम भूमदेन ने बौद्ध धर्म के बारे में गहन बातचीत आयोजित करने के लिए मंच द्वारा प्रदान किए गए अवसर की प्रशंसा की। उन्होंने प्रार्थना की कि सभी प्राणियों को शांति और समृद्धि प्राप्त हो।

अमेरिका स्थित कम्बोडियाई बौद्ध भिक्षु सोसायटी के अध्यक्ष प्रीह इद्दीमुनि मोएंग सांग ने कहा कि परम पावन और महासंघ की उपस्थिति में यहां आना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि उनके समूह ने हाल

ही में बोधगया में संपूर्ण त्रिपिटक का जाप पूरा किया है।

मंगोलिया के गैंडेन थेकचेनलिंग मठ के मठाधीश महामहिम खंबो नोमुन खान, गेशे जेत्सुन दोर्जे ने अपना संदेश भेजा जो यहां पढ़ा गया। उन्होंने २१वीं सदी में बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा करने के लिए ऐसी सभा आयोजित करने के लिए आयोजकों को बधाई दी।

यांगून के राज्य संघमहानायक सदस्य और म्यांमार के उप संघराजा वेन कुमदीनना ने अपनी शुभकामनाएं दीं।

रूस के कालमीकिया के काल्मिक बौद्धों के प्रमुख शादजिन लामा गेशे तेनज़िन चोदक ने अपनी शुभकामनाएं दीं और कहा कि इस असाधारण जगह में इस मंच में भाग लेना उनके लिए सम्मान की बात है। उनकी शुभकामना पत्र का अनुवाद तेलो तुल्कु ने किया।

वियतनामी बौद्ध संघ के प्रतिनिधि वेन त्रि मिंगज़ेन ने 'नमो शाक्यमुनि बुद्ध' कहकर भव्य आत्मा का आह्वान किया और टिप्पणी की कि अनित्यता के बारे में मुख्य शिक्षा का अर्थ है कि चीजें हमेशा बदलती रहती हैं। उपदेशों के पालन के महत्व पर अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले उन्होंने एक मिनट का ध्यान किया।

श्रीलंका के असगिरिया चैप्टर के सियाम महा निकाय के महायानके थेरो परम आदरणीय डॉ. वारकागोड़ा ज्ञानरत्न महायानके थेरो ने कहा कि धार्मिक सम्मेलन पूरी दुनिया में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन इस सम्मेलन में जो अलग विशेषता है वह यह कि यह सम्मेलन बौद्ध धर्म के जन्मस्थान में बुद्ध की अहिंसा और करुणा की शिक्षा कर रहा है, और इस तरह बुद्ध ने जो उपदेश दिया, हम उसका संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं।

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह के माननीय कार्यकारी पार्षद श्री ताशी नामग्याल ने लद्दाख के लोगों की ओर से शुभकामनाएं दीं और पाली और संस्कृत परंपराओं के बीच उत्साही संवाद को प्रोत्साहित किया।

भारत के अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने परम पावन के साथ ही विद्वानों, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का अभिवादन किया।

उन्होंने कहा, 'मैं इस सभा में उपस्थित होने और सभी को आशीर्वाद देने के लिए परम पावन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ऐसा करके हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं आभारी हूं कि पालि और संस्कृत परंपराओं को एक साथ लाने के परम पावन के दृष्टिकोण को पूरा करने वाले इस तरह के मंच आयोजित किए जा रहे हैं और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं ज्ञान और विद्वता की चर्चा में भाग ले रहा हूं। हम न केवल बुद्ध की शिक्षाओं को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करते हैं, बल्कि उन्हें नीति का आधार बनाने का भी प्रयास करते हैं। परम पावन दीर्घायु हों।

परम पावन ने जो कुछ पहले ही कहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे कहा-

'इस शुभ अवसर पर इस पवित्र स्थान पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जब बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने की बात आती है तो हमें केवल मठवासी चीवर पहनकर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अध्ययन और साधना करनी चाहिए। हमें अपने मन और भावनाओं की कार्यप्रणाली के बारे में सीखने की जरूरत है। आज, वैज्ञानिक भी मन और आंतरिक शांति पाने के साधनों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं।'

उन्होंने कहा, 'मन में सूक्ष्मता के भी विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे जाग्रत, नींद और स्वप्न की अवस्था। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने शरीर को इच्छाधारी बना लिया है और अपनी इच्छानुसार यहां-वहां जाते रहते हैं। धर्म की साधना केवल अनुष्ठान करना और प्रार्थना करना भर नहीं है। इसमें हमारे दिमाग को प्रशिक्षित करने और हमारी भावनाओं पर काबू पाने की तकनीकें शामिल हैं।'

'तिब्बती परंपरा में मुख्यधारा और महायान दोनों परंपराओं से बुद्ध के संपूर्ण उपदेश लिए गए हैं, जिसमें मन की सूक्ष्मता की व्याख्याएं शामिल हैं। धन्यवाद।'

आईबीसी के महासचिव वेन खेंसूर जांगचुब चोएडेन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

उन्होंने कहा, 'मैं परम पावन १४वें दलाई लामा के नेतृत्व वाले पवित्र संघ प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे आज सुबह के सत्र में व्याख्यान देने वाले सभी महानुभावों- परम पावन दलाई लामा, गदेन त्रि रिनपोछे, अरुणाचल के मुख्यमंत्री और कई संघ समुदायों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज जब हम यहां इस सबसे पवित्र स्थान पर एकत्र हुए हैं, तो हमें पवित्र धर्म में निहित अंतर्दृष्टि और हमारे जीवन में अपनेपन और उद्देश्य की भावना के लिए धर्म का आभारी होना चाहिए।

'आइए हम इस बैठक की विविधता को पहचानने का प्रयास करें। आइए, हम इस सभा का उपयोग सीखने, साझा करने और अपनी आपसी समझ को बेहतर बनाने के लिए करें। आइए हम एक-दूसरे के लिए अपने दिल खोलें।

'मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मंच को समर्थन दिया है। साथ ही उन लोगों को भी धन्यवाद, जिन्होंने संघ के सदस्यों के लिए आवास उपलब्ध कराया है। सभी स्वयंसेवकों को उनके अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद और आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप बोधगया से ऊर्जावान होकर और प्रेरणा ग्रहण करके जाएंगे।'

◆ सिक्किम के मुख्यमंत्री ने परम पावन दलाई लामा का स्वागत किया

dalailama.com, ११ दिसंबर, २०२३

गंगटोक, सिक्किम, भारत। दिल्ली से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा होते हुए सिक्किम जा रहे परम पावन दलाई लामा ने ११ दिसंबर की सुबह दिल्ली से उड़ान भरी। हवाई अड्डे पर सिक्किम सरकार के धार्मिक मामलों के मंत्री वेन सोनम लामा ने उनका स्वागत किया। बागडोगरा से वह हेलीकॉप्टर से गंगटोक के लिए उड़े। गंगटोक के लिबिंग हेलीपैड पर पहुंचने पर उनकी अगवानी सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग, मुख्य सचिव श्री विजय भूषण पाठक, पुलिस महानिदेशक श्री अमरेंद्र कुमार सिंह और कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने किया। अगवानी करने में गंगटोक, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग के तिब्बती प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

जैसे ही परम पावन हेलीपैड से चले गए सड़क पर लगभग एक दर्जन स्थानीय मठों के भिक्षुओं के समूह ने उनका अभिवादन किया। उनमें से कई ने अपनी औपचारिक टोपी पहनी और अभिवादन में झांझ, ड्रम और सींग बजाए। मुख्य सड़क पर ताशी शोल्पा नर्तकों के एक समूह ने स्वागत में नृत्य किया, जबकि स्थानीय सिक्किमी और तिब्बती लोग सड़क पर खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे अपने हाथ जोड़कर अभिवादन के रूप में सफेद या पीले रेशम के खटक हिला रहे थे और फूल, धूप आदि अर्पित कर रहे थे। तिब्बती महिलाएं समूहों में खुशी से नाच-गा रही थीं। एक अन्य समूह ने एक चीयरलीडर का पीछा करते हुए उत्साहपूर्वक चिल्लाते हुए कहा, 'दलाई लामा अमर रहें'।

होटल के दरवाजे के बाहर सिक्किम पुलिस गार्ड के सदस्यों ने हथियार झुकाए और परम पावन ने सलामी ली। दरवाजे पर उन्हें अभिवादन के रूप में पारंपरिक 'चेमा चांगफू' पेश की गई। लॉबी के अंदर ही सिक्किम सरकार के बाकी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। सुइट के दरवाजे पर परम पावन का स्वागत उनके बड़े भाई ग्यालो थोंडुप ने किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य उन्हें अभिवादन करने पहुंचे।

दोपहर के भोजन के तुरंत बाद सिक्किम के राज्यपाल, महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने परम पावन से शिष्टाचार भेंट की।

◆ परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की ३४वीं वर्षगांठ पर कशाग का वक्तव्य

dalailama.com,१० दिसंबर, २०२३

परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की ३४वीं वर्षगांठ के विशेष अवसर पर कशाग परम पावन दलाई लामा के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव प्रकट करता है। कशाग इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहां मौजूद गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों का भी गर्मजोशी से स्वागत करना चाहता है। हम सभी निर्वासित तिब्बती समुदायों और विशेष रूप से तिब्बत के अंदर रहने वाले तिब्बतियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं।

परम पावन दलाई लामा को विश्व शांति का प्रचार करने और सुखी जीवन के लिए सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने में उनके असाधारण नेतृत्व को देखते हुए उन्हें प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परम पावन ने बहुत कम उम्र से ही करुणा और परोपकार की निरंतर और अनुकरणीय साधना के आधार पर इन सभी गुणों को संचित किया। यह पुरस्कार परम पावन दलाई लामा के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में अहिंसक मुक्ति साधना के प्रति तिब्बती लोगों की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी मान्यता प्रदान करनेवाला है।

नोबेल पुरस्कार के संस्थापक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल को औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में ही डायनामाइट का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया था। विनाशकारी गोला-बारूद और युद्ध के लिए अपने वैज्ञानिक आविष्कार के दुरुपयोग पर उन्हें गहरा अफसोस और दुःख हुआ। इसलिए, उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धियों और शांति में काम के लिए दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से से नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना की। इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत १९०१ में हुई।

परम पावन दलाई लामा ने इस बात पर जोर दिया है कि करुणा और ज्ञान की साधना पूरी मानवता के लिए उपयोगी है। विशेष रूप से यह राष्ट्रीय मामलों को संचालित करने वाले जिम्मेदार लोगों, जिनके हाथों में शांतिपूर्ण दुनिया की संरचना बनाने की शक्ति और अवसर निहित है, के लिए बेहद उपयोगी है। परम पावन ने बार-बार ज़ोर देकर कहा है कि प्रत्येक मनुष्य संघर्ष और घृणा से मुक्त होकर शांति से रहना चाहता है। परम पावन ने यह भी दोहराया है कि समस्याओं को स्पष्ट और शांत मन से सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है। जबकि घृणा, ईर्ष्या और क्रोध हमारी निर्णय की भावना को ओझल कर देते हैं।

पिछली सदी को युद्ध और रक्तपात की सदी कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित संघर्षों में २० करोड़ से अधिक लोग मारे गए। वर्तमान सदी को संवाद और शांति की सदी बनाना मानवता की सामूहिक आकांक्षा है। १० दिसंबर को नोबेल शांति पुरस्कार दिवस और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का एक साथ मनाया जाना दुनिया भर में शांति और मानवाधिकारों के लिए मानवता की आम आकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि, यह आकांक्षा हमसे दूर होती जा रही है। पश्चिम एशिया के संघर्ष में जारी तबाही का कोई अंत नहीं दिख रहा है और रूस का यूक्रेन पर आक्रमण के अलावा अन्य हिंसक संघर्ष गंभीर वैश्विक चिंता के विषय बने हुए हैं। इसके अलावा, सभी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपना सैन्य

बजट बढ़ा रहे हैं, गुट बना रहे हैं और सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। कम्युनिस्ट और अधिनायकवादी देश मानवता की मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करके संहारक शासकीय नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें प्रचारित कर रहे हैं।

परम पावन दलाई लामा ने कहा कि गजा में फलस्तीन और इज़रायल के बीच संघर्ष कल्पना से परे है। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि धर्म और सिद्धांतों को मानने का दावा करने वाले लोगों के बीच इस तरह की हिंसा हो रही है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के ठीक चार दिन बाद परम पावन ने कहा था कि हमारी दुनिया इतनी अधिक निर्भर हो गई है कि दो देशों के बीच हिंसक संघर्ष अनिवार्य रूप से शेष विश्व को प्रभावित करता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध अब पुराना तरीका हो चुका है और अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। परम पावन ने कहा कि उन्होंने सभी लोगों को भाई-बहन मानकर मानवता की एकता की भावना विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

पिछले महीने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार ने एक श्वेत-पत्र जारी किया, जिसका शीर्षक है, 'नए युग में ज़िज़ांग के शासन पर सीपीसी नीतियां: दृष्टिकोण और उपलब्धियां'। चीन सरकार का दावा है कि 'ज़िज़ांग की सामाजिक और आर्थिक प्रगति देश की उत्कृष्ट उपलब्धियों का प्रतीक है, जो आधुनिकीकरण के चीनी मॉडल को लेकर दुनिया की छत पर बनाई गई है'।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) अब 'एकत्ववादी समुदाय के रूप में चीनी राष्ट्रीयता की मजबूत भावना पैदा करने, चीनी भाषा को बढ़ावा देने, तिब्बती बौद्ध धर्म का चीनीकरण करने और समाजवादी मूल्यों को विकसित करने के नाम पर तिब्बती पहचान को खत्म करने का काम सख्ती से कर रही है। सीसीपी अधिकारियों द्वारा तिब्बती लोगों पर इस तरह की सख्ती और उनका उत्पीड़न अद्वितीय और अभूतपूर्व है।

चियांग काई-शेक के नेतृत्व वाली चीन गणराज्य की सरकार द्वारा १९३५ और १९३६ में पराजित कर दिए जाने पर कम्युनिस्ट लाल सेना खाम में चाकसम और कर्जे से पीछे हटी और अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की ओर न्गाबा, बरखम, काखोग, ट्रोचू, सुंगचू, ज़ोएगे और अमदो में थेवो में भाग गई। भूख से त्रस्त चीनी सेना ने तिब्बतियों से भोजन और संपत्ति लूट ली और मठों से धार्मिक कलाकृतियां लूट लीं। माओत्से तुंग ने बाद में पत्रकार एडगर स्नो के सामने स्वीकार किया कि तिब्बत से यह हमारा एकमात्र 'विदेशी ऋण' है। इसके अलावा, जब लुटेरी चीनी सेना के खिलाफ विद्रोह किया तो कई तिब्बती मारे गए। उदाहरण के लिए, सुंगचू के मुतो गांव में २७ परिवारों के ११८ तिब्बतियों की उस समय हत्या कर दी गई जब उन्होंने अपना अनाज लूट रही चीनी सेना का विरोध किया था। लाल सेना की तीन हमलावर टुकड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले तिब्बती क्षेत्रों को अपने इतिहास का अभूतपूर्व विनाशकारी अकाल से रू-ब-रू होना पड़ा था।

पीआरसी के तिब्बत पर आक्रमण और कब्जे के परिणामस्वरूप १९८० तक अनुमानित १२ लाख तिब्बतियों की मौत हो गई और ६००० से अधिक मठ नष्ट कर दिए गए। यह जनसंहार २०वीं सदी की शुरुआत के अर्मेनियाई नरसंहार से भी अधिक विनाशकारी था।

श्वेत-पत्र केवल 'तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र" (टीएआर)' के बारे में बात करता है और चीनी प्रांतों में शामिल तिब्बती क्षेत्रों की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। हालांकि, तिब्बती नस्ल को ख़त्म करने की नीति पूरे तिब्बत में लागू की जा रही है। अंतर-नस्लीय आदान-प्रदान, संचार और एकीकरण के नाम पर लागू की गई चाल ग्रामीण और देहाती समुदायों, स्कूलों और मठों सहित समुदाय के हर वर्ग में बड़े पैमाने पर तिब्बतियों का चीनीकरण कर रहा है।

तिब्बती क्षेत्रों में चीनी कैडरों की नियुक्ति में तेजी से वृद्धि हुई है। हालांकि श्वेत पत्र में केवल 'तिब्बत की सहायता के लिए भेजे गए १०,००० से अधिक अधिकारियों' का उल्लेख है, लेकिन इसने विशिष्ट क्षेत्रों या अन्य रूपों में की गई नियुक्तियों की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया है। चीनी सरकार ने तिब्बतियों की युवा पीढ़ी को हान चीनी मूल में विलय करने के लिए 'टीएआर' से लगभग ९५% कॉलेज स्नातकों को रोजगार देने के लिए मुख्य भूमि चीन के १७ प्रांतों में नौकरी प्लेसमेंट केंद्र स्थापित करने के अपने प्रयासों के बारे में उल्लेख किया है।

इसी तरह श्वेत-पत्र में कानूनी दायित्व के रूप में जातीय एकता के नाम पर पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की गई। लेकिन श्वेत-पत्र में पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबी उन्मूलन के बहाने तिब्बतियों के बड़े पैमाने पर किए गए जबरन पुनर्वास का उल्लेख नहीं किया गया है। श्वेत-पत्र में दावा किया गया है कि २,००,००० से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से उपर लाया गया है। माना जाता है कि उन्हें अपने गृहनगर के बाहर नौकरियां मिलीं। बड़ी संख्या में युवा तिब्बतियों को समूहों में चीन ले जाए जाने की खबरें आती रहती हैं। उदाहरण के लिए छोचांग तिब्बत स्वायत्त प्रान्त में कृषि और देहाती क्षेत्रों में ४०,००० श्रमिकों को रोजगार खोजने में सहायता करने के लिए एक परियोजना के हिस्से के रूप में ६४० श्रमिकों को मुख्य भूमि चीन के कुछ हिस्से के विभिन्न स्थानों पर नूडल रेस्तरां खोलने में मदद करने के लिए १० लाख युआन का ऋण दिया गया है। यह जानकारी खुद चीनी सरकार ने दी हैं।

चीनी सरकार तिब्बती बौद्ध धर्म के चीनीकरण करने का काम तेजी से चला रही है। यह तिब्बती भिक्षुओं को समाजवादी मूल्यों का सख्ती से पालन करने और महान मातृभूमि, चीनी राष्ट्र, चीनी संस्कृति, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच पहचानों को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। इसका लक्ष्य चीनी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने और तिब्बती भिक्षुओं और भिक्षुणियों के बीच कम्युनिस्ट विचारधारा को स्थापित करने के लिए नालंदा परंपरा पर आधारित तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन की नींव को कमजोर करना है। संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग के निर्देशन में एक दशक से अधिक समय से 'तिब्बती बौद्ध सूत्रों की व्याख्या पर पुस्तकों' का प्रकाशन कर रहा है। यह वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बौद्ध सिद्धांतों को विरूपित करना है।

'लोकतांत्रिक प्रबंधन समितियों' ने मठों और धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन के हर पहलू को विनियमित और निगरानी करने के लिए तिब्बत में तिब्बती मठों और भिक्षुणी विहारों में कम्युनिस्ट पार्टी की शाखाएं

स्थापित की हैं। 'चीनी राष्ट्रीयता की चेतना को विकसित करने' के लिए भिक्षुओं को तिब्बती समाज में राष्ट्रीय चेतना, नागरिकता चेतना और कानून के नियम की चेतना से अवगत होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तिब्बतियों को मठों और घरों की छतों पर चीनी झंडा फहराने के लिए मजबूर किया जाता है। इसी तरह तिब्बतियों को माओ से लेकर शी तक पांच चीनी नेताओं की तस्वीरें मठों, सार्वजनिक हॉलों और घरों में लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

श्वेत-पत्र में कहा गया है कि 'दलाई लामा और पंचेन रिनपोछेओं सहित पुनर्जन्म लेने वाले तिब्बती जीवित बुद्धों की देश के भीतर तलाश की जानी चाहिए, स्वर्ण कलश से लॉटरी निकालने की प्रथा के माध्यम से निर्णय लिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।' पीआरसी द्वारा आधिकारिक प्रचार राजनीतिक व्यामोह में फंसे चीनी नेताओं की मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। यह पुनर्जन्म के बौद्ध सिद्धांत की निर्लज्ज अस्वीकृति, धर्म की सेवा के लिए ट्रुलकु के पुनर्जन्म के उद्देश्यों को कुचलना और दुनिया भर में फल-फूल रहे तिब्बती बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति को लेकर अज्ञानता भी है।

चीनी सरकार का दावा है कि आम बोली और लिखी जाने वाली भाषा के तौर पर चीनी को बढ़ावा देने का उद्देश्य 'उत्कृष्ट पारंपरिक चीनी संस्कृति की रक्षा करना और साम्यवाद की भावना को विकसित करना है, जिसने चीनी राष्ट्र के लिए समुदाय की भावना के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद की है'। हालांकि, प्रचार के इस दिखावे के नाम पर तिब्बती भाषा को व्यवस्थित रूप से मिटाया जा रहा है। खाम और अमदो क्षेत्रों से मुख्य भूमि चीन के स्कूलों में तिब्बती छात्रों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण तेज हो गया है। चिंताजनक बात यह है कि तिब्बत में लगभग दस लाख प्राथमिक तिब्बती स्कूली बच्चों को जबरन उनके परिवारों और उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनके जीवन के तरीके से दूर करके बोर्डिंग स्कूलों में भर्ती कराया जा रहा है।

इसी तरह तिब्बत में सरकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षा में तिब्बती भाषा को हटा दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक विभागों के बीच आधिकारिक संचार का माध्यम तिब्बती से बदलकर चीनी कर दिया गया है। इसके अलावा, तिब्बती भाषा की सुरक्षा के लिए अभियान चलाने वाले लोगों को राजनीतिक अपराधी करार दिया जाता है और कारावास की सजा दी जाती है। रिपोर्टों से यह भी संकेत मिलता है कि कर्ज़े तिब्बती स्वायत्त प्रान्त' ने अगले साल से क्षेत्र के प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों तक में तिब्बती भाषा कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नोटिस जारी किया है। चूंकि स्कूलों में तिब्बती भाषा पढ़ाना प्रतिबंधित है और तिब्बती भाषा में कर्मचारी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसलिए तिब्बती भाषा के उपयोग के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह तिब्बती को इस धरती से एक जाति के रूप में मिटा देने का इरादा दिखता है।

श्वेत-पत्र साहित्यिक और कलात्मक कार्यों में तथाकथित उपलब्धियों के बारे में बात करता है। जैसे कि, नए युग में आगे बढ़ना, रेडियो, टीवी, प्रदर्शनियों और संग्रहालयों को देशभक्ति के शैक्षिक आधार के रूप में और सांस्कृतिक और नैतिक विकास के नाम पर चीनी संस्कृति की रक्षा करना। हालांकि, इसका तिब्बती धर्म, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और प्रचार-प्रसार से कोई लेना-देना नहीं है। बल्कि इससे साफ़ पता चलता है कि किस तरह तिब्बतियों को कम्युनिस्ट विचारधारा की प्रशंसा करने और उसे अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। अनेक परियोजनाओं में आर्थिक निवेश और प्राप्त परिणामों के बारे में सीसीपी के दावों के बावजूद इनका उद्देश्य तिब्बतियों की भलाई के लिए नहीं है। बल्कि, चीन सरकार को तिब्बत पर आसानी से नियंत्रण करने, तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने और तिब्बतियों पर निगरानी रखने की सुविधा प्रदान करना है। तिब्बती क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से में चले रहे तथाकथित प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण और राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण का ढोंग असल में औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा मूल निवासियों से भूमि छीन लेने वाला है।

पीआरसी की व्यापक चीनीकरण नीति के हिस्से के तौर पर श्वेत-पत्र में तिब्बत शब्द को हटाकर पिनयिन में 'ज़िज़ांग' किया गया है। इसके अलावा ल्हासा जैसे शहरों से लेकर गांवों तक के स्थानों के नाम तिब्बती से बदलकर चीनी किए जा रहे हैं। तिब्बत के स्थान पर 'ज़िज़ांग' शब्द का प्रयोग करने का पीआरसी का एकमात्र उद्देश्य तिब्बत को विश्व मानचित्र से गायब कर देना है। चीन उम्मीद करता है कि इसके बाद तिब्बत अपनी निराधार वैधता का दावा करने के लिए दुनिया के लोगों की यादों से मिट जाएगा।

चीन की तिब्बत नीति का उद्देश्य लगभग १४०० वर्षों की समृद्ध तिब्बती भाषा को नष्ट करना, बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जाति-शक्ति और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव के बिना समानता पर आधारित तिब्बती बौद्ध धर्म को खत्म कर इसके चीनी संस्करण की स्थापना, करुणा और अहिंसा से भरी तिब्बती संस्कृति का उन्मूलन और विशिष्ट तिब्बती जाति को बहुसंख्यक हान नस्ल में विलय कर देना है। ऐसी ग़लत गणना वाली रणनीतियां और गुमराह नीतियां अस्थिर हैं और विफल होने को ही अभिशप्त है। जब तिब्बतियों को भारतीय बौद्ध धर्म की नालंदा परंपरा और चीनी होशंग की ध्यान पद्धति में से एक को चुनने का सामना करना पड़ा तो सम्राट ट्रिसोंग डेट्सन ने भारतीय परंपरा का ही पालन करने का निर्णय लिया। सम्राट के इस निर्णय ने तिब्बत को बौद्ध आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप और गुणवत्ता में संरक्षित करने में मदद की है। ज्ञात हो कि चीनी होशंग की ध्यान पद्धति राजा ट्रिसोंग डेट्सन के दरबार के सर्वोच्च दरबारियों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि, यह पद्धति सैम्ये मठ के नियमों और साधना प्रक्रिया का उल्लंघन करती थी।

माओ की दमनकारी नीतियों के तहत तिब्बती पहचान का खात्मा हमारे इतिहास का सबसे काला अध्याय है। संपूर्ण विनाश के बावजूद परम पावन दलाई लामा के असाधारण नेतृत्व में और निर्वासन में तिब्बतियों की दृढ़ता और तिब्बत में हमारे भाइयों के दृढ़ संकल्प के कारण थोड़े समय के भीतर न केवल तिब्बती संस्कृति और धर्म को संरक्षित और प्रचारित किया गया, बल्कि आगे भी जारी रखा गया है। तिब्बती संस्कृति इस समय हिमालयी क्षेत्रों सहित दुनिया भर में जीवित है और फल-फूल रहा है।

हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से चीनी संविधान में उल्लिखित क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्वायत्तता के कानून के घोर उल्लंघन को तुरंत बंद करने और तिब्बती

पहचान को खत्म करने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों को बंद करने का आह्वान करते हैं। यदि चीनी सरकार इन नीतियों को नहीं बंद करती है तो यह तिब्बती लोगों के दिल और दिमाग में अपूरणीय घाव पैदा करेगा जो प्राचीन काल से पड़ोसी के रूप में तिब्बती और चीनी लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को प्रभावित करेगा। ७५ साल पहले ०९ अक्तूबर १९४८ को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत जनसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते सीसीपी को इस अंतरराष्ट्रीय कानून की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

अंत में हम इस आशा के साथ प्रार्थना करते हैं कि दुनिया भर में शांति कायम रहे और हर किसी को स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का आनंद मिले। हम परम पावन दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह अपना शेष जीवन विश्व शांति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में बिता सकें। तिब्बत के सत्य और अहिंसक उद्देश्य की जय हो।

कशाग

१० दिसंबर, २०२३

◆ सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने पेरिस में तिब्बत समाधान अधिनियम को एचएफएसी की मंजूरी पर चर्चा की

tibet.net, ०४ दिसंबर, २०२३

पेरिस। वियना में अपना आधिकारिक कार्यक्रम संपन्न करने के बाद केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ३० नवंबर को पेरिस पहुंचे। सिक्योंग का हवाई अड्डे पर तिब्बती सांसद थुप्टेन ग्यात्सो, ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिगज़िन चोएडॉन जेनखांग, पेरिस समन्वयक थुप्टेन छेरिंग और ब्यूरो डू तिब्बत के कर्मचारी, पेरिस-तिब्बती एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मा थिनले और स्थानीय तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

पेरिस में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का साक्षात्कार पेरिस के विभिन्न मीडिया संस्थानों के मीडिया कर्मियों द्वारा किया गया, जिनमें रेडियो फ्रांस इंटरनेशनेल के नथनेल चार्बोनियर, लिबरेशन से अरनॉड वाउलेरिन, रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल के जान वान डेर मेड, लेमोंडे के ब्रूनो फिलिप और इंटरनेशनल न्यूज चैनल फ्रांस २४ के पत्रकार शामिल थे।

सिक्योंग ने क्रमशः ०१ और ०२ दिसंबर को अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में पेरिस स्थित बौद्ध केंद्रों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ तिब्बती युवाओं के एक समूह से भी मुलाकात की। उन्होंने सीटीए की वी-टैग पहल में भाग लेने के माध्यम से तिब्बत मुक्ति साधना का पक्ष मजबूत करने के तरीके पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने तिब्बती युवाओं के दल के साथ तिब्बती पर्यावरण, धर्म, परंपरा और भाषा के महत्व के बारे में बात की।

०२ दिसंबर की दोपहर में निर्वासित तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रमुख ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से संबंधित सदन की समिति (एचएफएसी) से द्विदलीय रिजॉर्व तिब्बत ऐक्ट (तिब्बत समाधान अधिनियम) की हालिया मंजूरी और अन्य प्रमुख मुद्दों के बारे में पेरिस में तिब्बती समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'यह विधेयक दर्शाता है कि पीआरसी का यह दावा ऐतिहासिक रूप से कितना अविश्वसनीय है कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। यह विधेयक अमेरिकी विदेश मंत्रालय को गैंडेन फोडरंग सरकार सहित तिब्बती इतिहास, संस्कृति और संस्थानों के साथ सीपीसी के छेड़छाड़ का मुकाबला करने के लिए अधिकृत करेगा। इसके अलावा, सिक्योंग की बातचीत में परम पावन दलाई लामा के योगदान और उनकी विरासत, तिब्बत में चिंताजनक मानवाधिकार स्थिति, वर्तमान कशाग के राजनीतिक और प्रशासनिक उपक्रम और तिब्बत-चीन संघर्ष के समाधान में आम तिब्बतियों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को भी याद किया गया।

अपनी आधिकारिक यात्रा को समाप्त करने से पहले सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ०३ दिसंबर को तिब्बती वीकेंड स्कूल का दौरा किया और शिक्षकों के साथ बातचीत की।

◆ ताशी ल्हुनपो मठ ने भारत सरकार से तिब्बत के ११वें पंचेन लामा को रिहा करने के लिए चीन पर दबाव डालने की अपील की

tibet.net, ०५ दिसंबर, २०२३

नई दिल्ली। दक्षिण भारत में स्थित ताशी ल्हुनपो मठ ने नई दिल्ली स्थित भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय के साथ समन्वय करते हुए ०५ दिसंबर २०२३ को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में 'पंचेन लामा जागरुकता पहल' की शुरुआत की। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की योजना पंचेन लामा के जबरन गायब होने से उपजे मानवीय और सांस्कृतिक मुद्दों के बारे में अधिक जागरुकता लाने और उनकी रिहाई पर आम सहमति की दिशा में काम करने को लेकर बनाई गई थी।

इस कार्यक्रम में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग (केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के राष्ट्रपति) सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें सांसद सुजीत कुमार (तिब्बत पर सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच के संयोजक), सांसद सुशील कुमार मोदी (बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री), सांसद जामयांग छेरिंग नामग्याल, सांसद अनिल प्रसाद हेगड़े, सांसद चंदेश्वर प्रसाद और रिनचेन खांडो खिरमे (कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज- इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक) शामिल हुए।

इस अवसर पर ताशी ल्हुनपो मठ के मठाधीश ज़ीक्याब रिनपोछे और भिक्षु तेनज़िन थुप्टेन रबग्याल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

भारतीय संसद के सदस्यों ने अपने संबोधन में चीनी कम्युनिस्ट शासन द्वारा तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जे की निंदा की और महामहिम ११वें पंचेन लामा को चीनी कैद

से तुरंत रिहा करने का आह्वान किया।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने अपने संबोधन में ११वें पंचेन लामा के महत्व पर प्रकाश डाला और उनके पूर्ववर्ती महान १०वें पंचेन लामा के कार्यों और तिब्बत और तिब्बती लोगों के लिए उनके बलिदानों का विवरण दिया। इसके अलावा, उन्होंने परम पावन दलाई लामा और महामहिम पंचेन लामा को सूर्य और चंद्रमा के रूप में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक छोटे बच्चे, जो आज दुनिया में सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी के रूप में जाना जाता है, के अपहरण के सीसीपी के कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा की और चीनी सरकार से उसकी तत्काल रिहाई का आह्वान किया। सिक्योंग ने सदस्यों को तिब्बत के मुद्दे और तिब्बत के अंदर मौजूदा गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान समय में अपने पड़ोसी देशों के साथ-साथ दुनिया के लिए तिब्बत के भू-रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर ताशी ल्हुनपो मठ के मठाधीश भिक्षु ज़ीक्याब रिनपोछे ने निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा:

'आज, भारत के ताशी ल्हुन्पो मठ के मठाधीश के रूप में, तिब्बती लोगों, हिमालय क्षेत्र के बौद्ध भक्तों और मानवाधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, बच्चों के अधिकारों के समर्थक सभी लोगों और लाखों भक्तों की ओर से पंचेन लामा वंश, मैं भारत सरकार के संसद सदस्यों और इसके लोगों से ११वें पंचेन लामा की चीनी सरकार की पकड़ से रिहाई सुनिश्चित करने में आपके समर्थन की अपील करने के लिए हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हूं।

मैं तिब्बत की गंभीर स्थिति के संदर्भ में यह हार्दिक अपील करता हूं। तिब्बती लोगों, उनके आंदोलन और उनकी स्वतंत्रता पर लगाए गए गंभीर उत्पीड़न और अमानवीय प्रतिबंध लगातार बदतर होते गए। तिब्बत के लोग चुपचाप सहते हैं। आज, मेरी प्राथमिक अपील ११वें पंचेन लामा की तत्काल रिहाई और तिब्बत में तिब्बती लोगों की लंबे समय से चली आ रही दुर्दशा को संबोधित करने में आपकी मदद के लिए है।

१९८९ में, जब १०वें पंचेन लामा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, तो तिब्बत के भीतर और बाहर, ताशी ल्हुनपो मठ के भिक्षुओं और भक्तों ने परमपावन दलाई लामा से १०वें पंचेन लामा के वास्तविक पुनर्जन्म को पहचानने की प्रार्थना की, जैसा कि पुनः कहा गया है। तिब्बत में खोज समिति के बंदरगाह। परम पावन ने, इन रिपोर्टों की जांच के बाद, १४ मई, १९९५ को तिब्बत के नागचू लहरी काउंटी के बच्चे गेधुन चोएक्यी न्यिमा को १०वें पंचेन लामा का अवतार घोषित किया और उन्हें जेत्सुन तेनज़िन गेधुन येशी ल्हिनले फुंटसोक पाल सांगपो नाम दिया।

हालांकि, केवल तीन दिन बाद १७ मई, १९९५ को चीनी सरकार ने उस समय केवल ०६ वर्ष के हुए ११वें पंचेन लामा को तिब्बत स्थित उनके घर से उनके अधिकारों की अनदेखी करते हुए पकड़ लिया। तब से लेकर आज तक के २८ वर्षों में दुनिया ने न तो पंचेन लामा को देखा है और न ही उनके ठिकाने के बारे में जाना है। लोगों को यह भी पता नहीं है कि वह अब जीवित भी हैं या नहीं। चीनी सरकार ने तिब्बती लोगों और पंचेन लामा परंपरा के अनुयायियों के अधिकारों और भावनाओं की घोर उपेक्षा करते हुए झूठे पंचेन लामा के तौर पर ग्यालत्सेन नोरबू नाम के एक बच्चे को तिब्बतियों पर थोप दिया। थोपे हुए पंचेन लामा आज चीनी सरकार द्वारा राजनीतिक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कठपुतली बने हुए हैं।

इसलिए, हम निम्नलिखित छह सूत्रीय अपील पर आप भारतीय संसद के माननीय सदस्यों और भारतीय लोगों से दृढ़ता से समर्थन चाहते हैं :

पंचेन लामा की रिहाई के पक्ष में अभियान के तहत भारतीय सांसदों से छह सूत्रीय अपील

१. हम भारतीय संसद के सदस्यों से ३४ वर्षीय ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा की चीनी हिरासत से तत्काल रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करने और चीनी सरकार पर भारी दबाव बढ़ाने की अपील करते हैं। हम भारतीय संसद सदस्यों यह अनुरोध भी करते हैं कि वे संसद से ऐसे विधेयक को पारित कराएं, जिससे भारत सरकार के अधिकारियों को ११वें पंचेन लामा से मिलने और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता करने और इसे सत्यापित करने का अधिकार मिल जाए।

२. हम भारतीय सांसदों से अपील करते हैं कि वे चीनी सरकार की कैद में २८ वर्षों से उत्पीड़न की अकल्पनीय पीड़ा झेल रहे ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा को एक पुरस्कार से सम्मानित करें।

३. हम भारतीय सांसदों से अनुरोध करते हैं कि वे ११वें पंचेन लामा को जबरन गायब कर दिए जाने के बाद से अब तक की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सांसदों के हस्ताक्षर युक्त एक संयुक्त बयान जारी करें।

४. हम भारतीय संसद से आग्रह करते हैं कि वह चीन सरकार द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयासों के तहत तिब्बती बौद्ध लामाओं के पुनर्जन्म को मान्यता देने के मामले में हस्तक्षेप की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करे। इस प्रस्ताव में ११वें पंचेन लामा और उनके पूरे परिवार को लंबे समय से गायब रखने की भी निंदा की जानी चाहिए।

५. हम भारतीय सांसदों से अपील करते हैं कि वे १०वें पंचेन लामा के पुनर्जन्म की खोज के लिए गठित समिति के प्रमुख जड्रेल रिनपोछे समेत तिब्बत के सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की चीन से मांग करें। यह ज्ञात हो कि तिब्बत पर चीनी कब्जे के कारण १५८ तिब्बतियों ने आत्मदाह कर अपना विरोध व्यक्त किया है। इससे भी तिब्बत की गंभीर स्थिति का पता चलता है। हालिया घटनाओं में २५ फरवरी २०२२ को २५ वर्षीय छेवांग नोरबू और २७ मार्च २०२२ को ८१ वर्षीय ताफुन ने आत्मदाह कर लिया है। ये घटनाएं न्याय के लिए जारी लड़ाई की अहमियत को स्पष्ट करती हैं।

६. हम भारत सरकार और भारत के लोगों से अपील करते हैं कि वे परम पावन की तिब्बत वापसी और तिब्बत मुद्दे को बातचीत या मध्यम मार्ग दृष्टिकोण से हल करने की उनकी प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए समर्थन दें।

पंचेन लामा जागरुकता पहल' कार्यक्रम में तिब्बती सांसद नामग्याल डोलकर लाग्यारी और १७वीं निर्वासित तिब्बती संसद के सांसद भिक्षु गेशे अटोंग रिनचेन ग्यालछेन, एडवोकेट ताशी ग्यालसन, एलएएचडीसी लेह के अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी पार्षद शरछे खेंसूर जंगचुप, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव चोएडेन रिनपोछे, तिब्बती प्रतिनिधि, तिब्बत के भारतीय मित्र और मीडिया मित्र भी शामिल हुए।

◆ तिब्बतियों को माओ का १३०वां जन्मदिन मनाने के लिए मजबूर किया गया चीनी अधिकारियों ने माओ द्वारा तिब्बत पर १९५० के चीनी आक्रमण से पहले के तिब्बतियों को 'गरीब-वंचित' दिखाते हुए प्रचार -प्रसार किया है।

rfa.org/लोबसांग गेलेक, २८ दिसंबर, २०२३

चीनी अधिकारियों ने तिब्बत में स्थानीय लोगों को मंगलवार २६ दिसंबर को माओत्से तुंग का १३०वां जन्मदिन मनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने दिवंगत नेता को १९५० में 'तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति' का श्रेय दिया। हालांकि इस शांतिपूर्ण मुक्ति को निर्वासित तिब्बती अधिकारी चीनी आक्रमण और अवैध कब्जे की शुरुआत मानते हैं।

ल्हासा में एक युवा तिब्बती ने सुरक्षा कारणों से नाम न छापने की शर्त पर 'रेडियो फ्री एशिया' को बताया कि अधिकारियों ने माओ के जन्मदिन का इस्तेमाल 'तिब्बत के पिछले इतिहास के बारे में गलत जानकारी फैलाने और तथ्यों को विकृत करने के लिए किया, ताकि तिब्बती लोगों को इस दुष्प्रचार पर विश्वास हो सके।'

सूत्र ने कहा कि माओ का जन्मदिन मनाने के लिए आयोजित सार्वजनिक समारोहों में चीन द्वारा क्षेत्र पर आक्रमण और कब्जे को सही ठहराने के लिए चीनी आक्रमण से पहले के स्वतंत्र तिब्बत को पिछड़े और गरीब के रूप में दर्शाया जाता है। चीनी अधिकारी तर्क देते हैं कि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से हमेशा चीन का हिस्सा रहा है।

व्यक्ति ने कहा, 'चीनी अधिकारी इन आयोजनों में १९४० और १९५० के दशक के गरीब, वंचित तिब्बती परिवारों की तस्वीरों का इस्तेमाल और प्रसार करते हैं ताकि ऐसा लगे कि उस समय पूरा तिब्बत गरीबी से त्रस्त था।'

उन्होंने कहा, 'हालांकि यह सच है कि तिब्बत पर पहली बार चीन के आक्रमण के बाद से तिब्बत में विकास हुआ है, लेकिन तथ्य यह भी हैं कि दुनिया के कई स्वतंत्र देशों में भी इसी अवधि में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। और इसके लिए उन देशों में किसी प्रकार की कोई 'शांतिपूर्ण मुक्ति' के लिए अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ी।'

माओ की सरकार ने १९५० में तिब्बत पर आक्रमण किया और स्थानीय लोगों की जनकांति को पूरी से कुचलने के बाद १९५९ में इस क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया। इस कारण से तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा को अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में शरण लेनी पड़ी और हजारों तिब्बतियों को दुनिया में अन्य देशों में निर्वासन में पलायन करना पड़ा।

चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों की राजनीतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करते हुए तब से इस क्षेत्र पर कड़ी पकड़ बना ली है। इसी अक्तूबर में बीजिंग ने तिब्बत की स्वतंत्र पहचान को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसका नाम बदलकर रोमनीकृत नाम 'ज़िज़ांग' रख दिया है।

१७ सूत्री समझौता

तिब्बत के अंदरूनी सूत्र ने आरएफए को बताया कि माओ के जन्मदिन पर अपने प्रचार अभियान के दौरान चीनी अधिकारी फिर से इस विचार को बढ़ावा दे रहे थे कि १९५१ में दलाई लामा ने बीजिंग के साथ '१७ सूत्रीय समझौते' पर हस्ताक्षर किए थे और माओ को एक टेलीग्राम में वादा किया था कि वह इसका पालन करेंगे।

हालांकि, विशेषज्ञों और अधिकार समूहों का कहना है कि परम पावन दलाई लामा को आक्रमणकारी चीनी बलों के दबाव में दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। चीनी बलों ने धमकी दी थी कि अगर समझौते के दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए जो तिब्बत के पर पूर्ण रूप से आक्रमण कर दिया जाएगा। हालांकि दलाई लामा ने वहां से पलायन कर तिब्बत की सीमा के ठीक पार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में निर्वासन में पहुंचने के बाद समझौते को अस्वीकार कर दिया था। सूत्र ने कहा कि इस समय तिब्बतियों के लिए तनावपूर्ण समय है। कई लोगों को अपनी जुबान बंद रखने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि स्थानीय चीनी अधिकारी माओ के जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'कोई भी तिब्बती जो तिब्बत के अतीत, विशेष रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में तिब्बत के इतिहास के बारे में वास्तविक तथ्यों को सार्वजनिक करने की कोशिश करता है, उसे तुरंत चीनी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है।'

तिब्बत नीति संस्थान के निदेशक दावा छेरिंग ने कहा कि माओ के जन्मदिन पर जबरन जश्न मनाया जाना विशेष रूप से विकृत प्रतीत होता है, क्योंकि तिब्बती अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पूर्वजों के खिलाफ कुछ सबसे भयंकर अत्याचार माओ के शासन के दौरान ही हुए थे।

छेरिंग ने आरएफए को बताया, 'तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति' वास्तव में चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत पर आक्रमण् कर इस देश पर कब्ज़ा था। चीनी बलों ने कब्जे का विरोध करने वाले तिब्बतियों का क्रूरता से दमन किया और असहाय तिब्बतियों को १७ सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया।'

भारत के धर्मशाला स्थित तिब्बती सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के शोधकर्ता न्यिमा वोएसर ने कहा कि माओ के १९५० के आक्रमण के बाद से तिब्बत में चीनी दमनकारी नीतियों के कारण १० लाख से अधिक

तिब्बतियों के मारे जाने का अनुमान है।

वोएसर ने कहा, 'साल दर साल तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों का हनन बद से बदतर होता जा रहा है और हाल-फिलहाल इसके कम होने का कोई संकेत नहीं है।'

◆ सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने २७वें हिमालय महोत्सव में भारत-तिब्बत संबंधों की स्थिरता के लिए आशा व्यक्त की

tibet.net, ११ दिसंबर, २०२३

धर्मशाला। भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) ने रविवार को तिब्बती इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (टीआईपीए) के सभागार में परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य में दो दिवसीय २७वें हिमालय महोत्सव का आयोजन किया।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने महोत्सव के आधिकारिक कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। अन्य विशिष्ट हस्तियों में मुख्य अतिथि के रूप में नगरोटा के विधायक और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री मंत्री श्री रघुबीर सिंह बाली और विशिष्ट अतिथि के तौर पर धर्मशाला नगर निगम की महापौर श्रीमती नीनू शर्मा उपस्थित रहीं।

अपने संबोधन में सिक्योंग ने इस आयोजन के महत्व पर बात करते हुए कहा कि यह धर्मशाला के निवासियों और तिब्बतियों को विभिन्न कलात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान का जश्न मनाने के लिए एक मंच पर एक साथ लाता है। सिक्योंग ने दर्शकों को भारत-तिब्बत के प्राचीन संबंधों से अवगत कराया और सदियों से चले आ रहे संबंधों के बारे में बातचीत की।

तिब्बतियों के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता ने भारत से तिब्बती लिपि की व्युत्पत्ति और इसी लिपि के आधार पर तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरूआत पर प्रकाश डाला। भारत के साथ इतने महत्वपूर्ण संबंध के बारे में सिक्योंग ने कहा, 'हमें यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे पास प्राचीन भारतीय ज्ञान के एक हिस्से का भंडार हैं।'

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की स्थापना पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि तिब्बती समुदाय दुनिया में पूर्ण लोकतांत्रिक और राजनीतिक संरचना वाला एकमात्र निर्वासित समुदाय है।

निर्वासित तिब्बती नेता ने उसी दिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले मानवाधिकार दिवस के बारे में भी बात की। उन्होंने इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ के दौरान, जब तिब्बत में तिब्बतियों को राजनीतिक रूप से कोई स्थान नहीं है, तिब्बतियों के प्रति दयालुता के लिए भारत सरकार, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार और भारत के लोगों का आभार व्यक्त किया। अपना संबोधन समाप्त करने से पहले सिक्योंग ने भारत-तिब्बत संबंधों में विशेष रूप से दोनों देशों के समान हित के अवसरों के स्थायित्व के लिए आशा व्यक्त की।

यह उत्सव परम पावन दलाई लामा की शांति पहलों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता के तौर पर १० दिसंबर १९८९ को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में वर्ष १९९५ में शुरू किया गया था। यह सांस्कृतिक उत्सव विशेष रूप से शांति पहल का प्रतीक है और इसका उद्देश्य स्थानीय भारतीयों और तिब्बती समुदाय के बीच अंतर-सांप्रदायिक संपर्क और दोस्ती को मजबूत करना है, जबकि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच प्रशंसा और समझ को बढ़ावा देना है।

◆ 'स्वीडिश पार्लियामेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर तिब्बत' ने तिब्बत पर प्रस्ताव रखा

tibet.net, ०५ दिसंबर, २०२३

लंदन। 'स्वीडिश पार्लियामेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर तिब्बत' ने स्वीडिश संसद में तिब्बत पर तीन अलग-अलग प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव-१५२९, २२०७ और २४०२ काफी अभूतपूर्व हैं और स्वीडन में तिब्बत के लिए बेहतर समझ और समर्थन प्रदर्शित करता हैं। ये प्रस्ताव (१) परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म, (२) स्वीडन की सरकार तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन, अनिवार्य आवासीय स्कूलों और चीन सरकार को तिब्बती प्रतिनिधियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के मुद्दे को चीन के समक्ष उठाएगी; और (३) स्वीडन की सरकार तिब्बत के लिए यूरोपीय संघ के विशेष समन्वयक की नियुक्ति का यूरोपीय संघ के स्तर पर समर्थन के लिए काम करेगी।

लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय स्वीडन में सीटीए का प्रतिनिधित्व करता है। इस साल सितंबर की शुरुआत में तिब्बत मैत्री समूह की अध्यक्ष मार्गरेटा सेडरफेल्ट की अध्यक्षता में समूह के ग्यारह सांसद भारत के धर्मशाला में तिब्बती लोकतंत्र दिवस के समारोह में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। यहां उन्होंने परम पावन दलाई लामा से भी मुलाकात की। स्वीडिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की धर्मशाला यात्रा का आयोजन लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय और डीआईआईआर द्वारा किया गया था।

अक्तूबर २०२२ में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग की स्वीडन की पहली यात्रा भी लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान स्वीडन के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति और नई संसद में तिब्बत मैत्री समूह का नए सिरे से गठन भी हुआ था।

नवंबर २०२२ में तीन तिब्बती सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत द्वारा प्रायोजित स्वीडन का दौरा किया था। स्वीडन द्वारा यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता के दौरान लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय ने 'स्वीडिश पार्लियामेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर तिब्बत' के सहयोग से जून २०२३ में तिब्बत के पर्यावरण और तिब्बत और चीन के अनसुलझे संघर्ष पर स्वीडिश संसद में एक वार्ता आयोजित की थी।

लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रयासों को स्वीडन में तिब्बती समुदाय और स्वीडिश-तिब्बत समिति द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया जाता है। इस काम में दोनों सक्रिय हैं और देश में इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए दृढ़ता से सहयोग करते हैं।

◆ बीजिंग में आयोजित २४वें ईयू-चीन शिखर सम्मेलन के दौरान तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठा

tibet.net, ०८ दिसंबर, २०२३

ब्रुसेल्स। गुरुवार ०७ दिसंबर २०२३ को २४वां यूरोपीय संघ-चीन शिखर सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित हुआ। २०१९ के बाद यह पहला ऑफलाइन शिखर सम्मेलन था।

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च प्रतिनिधि जोसेप बोरेल ने इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की।

शिखर सम्मेलन के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अपनी टिप्पणी में कहा, 'यूरोपीय संघ की नीतियों में मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता सार्वभौमिक हैं और हम मानवाधिकार मामलों पर कभी भी आंखें नहीं मूंदेंगे। इसी कारण से आज हमने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे विशिष्ट मामलों पर चिंता जाहिर की और इस पर प्रकाश डाला है।

यूरोपीय संघ-चीन शिखर सम्मेलन के अंत में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष की टिप्पणियों का बड़े मजबूत राजनीतिक संकेत के रूप में स्वागत करते हुए तिब्बती प्रतिनिधि रिगज़िन जेनखांग ने कहा, 'इस तरह की घोषणा से पता चलता है कि यूरोपीय संघ तिब्बत से संबंधित मुद्दों को कितना महत्व देता है और यह उनके एजेंडे में शीर्ष पर बना हुआ है।'

ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिगज़िन जेनखांग ने यूरोपीय संघ के नेताओं को बीजिंग जाने से पहले पत्र लिखकर उनसे शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी नेताओं के साथ तिब्बत के मुद्दे को उठाने का आग्रह किया था।

पिछला यूरोपीय संघ-चीन शिखर सम्मेलन ०१ अप्रैल २०२३ को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुआ था।

◆ डिप्टी स्पीकर के नेतृत्व में तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में तिब्बत के पक्ष में अभियान शुरू की

tibet.net, १३ दिसंबर २०२३

नई दिल्ली। भारतीय संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के समय से तालमेल बिठाते हुए निर्वासित तिब्बती संसद की स्थायी समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने संसद की डिप्टी स्पीकर डोल्मा छेरिंग तेखांग के नेतृत्व में नई दिल्ली में तिब्बत के पक्ष में अभियान की शुरुआत की। प्रतिनिधिमंडल में सांसद तेनपा यारफेल और छानेछांग धोंडुप ताशी भी शामिल रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा, उपाध्यक्ष श्री केर्सी कैखुशरू देबू के अलावा आयोग के सदस्य श्री धन्यकुमार जिनप्पा डुंडे और श्रीमती रिनचेन ल्हामो जैसी उल्लेखनीय गणमान्य हस्तियों के साथ बातचीत की। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्यसभा सदस्य (एमपी) श्री (डॉ.) लंकाप्पा हनुमंतैया, दिल्ली विधानसभा के सदस्य (एमएलए) श्री अजय दत्त और अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत की। इन बैठकों में प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय से ताशी डेकी और तिब्बती संसदीय सचिवालय से तेनज़िन चोयिंग मौजूद थे।

दिन की शुरुआत नई दिल्ली के कोनराड एडेनॉयर फाउंडेशन के कार्यालय में एक बैठक से हुई, जहां तिब्बती सांसदों ने फाउंडेशन के निदेशक डॉ. एड्रेन हैक और कार्यक्रम प्रबंधक आशीष के साथ बातचीत की। चर्चाएं भविष्य के संभावित सहयोग पर केंद्रित थीं, जिसके दौरान तिब्बती सांसदों ने उन्हें दिल्ली की अपनी यात्रा के उद्देश्य से अवगत कराया और तिब्बत में वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति पर प्रकाश डाला। इसके बाद, प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के लिए रवाना हुआ, जहां उन्हें इसके निदेशक ने स्मारक और संग्रहालय दिखाया। उन्हें इसकी केंद्रीय मूर्तिकला,

वीरता की दीवार और अन्य उल्लेखनीय पहलुओं के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

इसके बाद, उनकी बैठक भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा, उपाध्यक्ष श्री केर्सी कैखुशरू देबू और आयोग के सदस्य श्री धन्यकुमार जिनप्पा डुंडे और श्रीमती रिनचेन ल्हामो के साथ हुई।

अतिरिक्त बैठकें दिन भर चलीं। इन बैठकों में राज्यसभा सदस्य (एमपी) श्री (डॉ.) लंकाप्पा हनुमंथैया और दिल्ली विधानसभा के सदस्य (एमएलए) श्री अजय दत्त भी शामिल रहे। इन व्यस्तताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल ने शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भी दौरा किया।

उपरोक्त प्रमुख गणमान्य हस्तियों के साथ अपनी बैठकों के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक साक्ष्यों और संप्रभु इतिहास से भरपूर तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बताया और इस देश को 'चीन के कब्जे वाले राष्ट्र' के रूप में मानने की वकालत की। उन्होंने चीन के झूठे कथानकों का समर्थन करने से परहेज करने का आग्रह किया जो तिब्बतियों को अल्पसंख्यक के रूप दुनिया के सामने रखता करता है। चीन का झूठा कथानक तिब्बत पर कब्जे को बीजिंग का आंतरिक मुद्दा बताता है और तिब्बत को चीन का हिस्सा बताता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का समर्थन तिब्बत पर चीन के साम्राज्यवादी आधिपत्य को सही ठहराता है, तिब्बतियों को चीन के अधीन करता हैं और उन्हें अधिक सार्थक स्वतंत्रता के लिए बातचीत करने से महरूम करता है।

इसके अलावा, उन्होंने गणमान्य हस्तियों से आग्रह किया कि वे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क

कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) से अनुरोध करें कि वे तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाली चीन सरकार की नीतियों पर वैज्ञानिक शोध अध्ययन कराए। इस शोध अध्ययन में वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के नकारात्मक प्रभाव को उजागर किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने इन हस्तियों से तिब्बत में स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों को जाने की अनुमति देने, तिब्बत में राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संघ और मानवाधिकार रक्षकों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूतों को जाने देने चीन पर दबाव डालने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल ने ११वें पंचेन लामा गेधुन चोएक्यी न्यिमा सहित सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों की बिना शर्त रिहाई के लिए भी चीन पर दबाव बनाने का आह्वान किया। ११वें पंचेन लामा का १७ मई, १९९५ को अपहरण कर लिया गया और तब से उनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तिब्बत-चीन संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय और अनसुलझी प्रकृति का मानने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गणमान्य हस्तियों से तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त करने और चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैग्निट्स्की अधिनियम को अपनाने के आह्वान में वैश्विक नेताओं के साथ शामिल होने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बती लोगों के वैध प्रतिनिधि (केंद्रीय तिब्बती प्रशासन) को मान्यता देने, ल्हासा में स्वतंत्र तिब्बत के जमाने की सरकार को बहाल करने के साथ इन दोनों संस्थाओं के साथ आधिकारिक और राजनयिक संबंधों को जोड़ने और गहरा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से सभी उपलब्ध मंचों पर तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपनी चिंताएं व्यक्त करने और आवाज उठाने का भी आग्रह किया।

◆ यूरोपीय संघ की संसद में चीन द्वारा संचालित औपनिवेशिक शैली के आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों को जबरन भर्ती करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित

tibet.net, १४ दिसंबर २०२३

ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ की संसद ने गुरुवार को भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें तिब्बत में चीन के सरकारी आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों को दमनकारी ढंग से जबरन भर्ती करने की निंदा की गई है। यह प्रस्ताव यूरोपीय सांसदों द्वारा बुधवार देर रात आयोजित एक जोरदार बहस के बाद पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में ४७७ वोट पड़े, विपक्ष में १४ वोट पड़े और ४५ लोग अनुपस्थित रहे।

हालांकि यह प्रस्ताव लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों को जबरन चीनी संस्कृति में विलय करने के मामले पर केंद्रित है, लेकिन यह शी जिनपिंग के शासन के तहत तिब्बत में लगातार बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति को भी उठाता है।

प्रस्ताव में चीनी सरकार से तिब्बत में आवासीय स्कूल प्रणाली को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया गया है और ईयू और सदस्य राज्यों से आवासीय स्कूलों में तिब्बती बच्चों को भर्ती करने में शामिल रहे चीनी अधिकारियों के खिलाफ निर्धारित प्रतिबंध कानूनों को लागू करने का आग्रह किया गया है।

यह प्रस्ताव प्रस्ताव रेन्यू समूह के सांसद सलीमा येनबौ द्वारा सदन में पेश किया गया। येनबौ इस साल मार्च में धर्मशाला का दौरा करने वाले यूरोपीय संघ के संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल का अन्य राजनीतिक समूहों ने समर्थन किया था।

ब्रुसेल्स स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि जेनखांग ने प्रस्ताव का स्वागत किया और चीनी सरकार द्वारा संचालित आवासीय स्कूलों में लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों को जबरन भर्ती करने के अभियान पर समय रहते कदम उठाने के लिए यूरोपीय संघ की संसद की सराहना की। यह प्रस्ताव चीनी सरकार द्वारा बच्चों के अधिकार सहित तिब्बती लोगों के मौलिक अधिकारों के निरंतर और गंभीर उल्लंघन पर प्रकाश डालता है।

◆ इंडिया सोशल फोरम में चला तिब्बत जागरुकता अभियान

tibet.net, ०४ दिसंबर, २०२३

पटना (बिहार)। नित नवीन होते वैश्विक समाज में राष्ट्रों को ऐसी-ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका अस्तित्व नष्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसे मंच के रूप में उभरा है, जहां दुनिया भर के नागरिक समाज मौजूदा संकट का सर्वमान्य समाधान खोजने के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। यह दुनिया भर में जन आंदोलनों और नागरिक समाज संगठनों की सामूहिक शक्ति को विकसित करने, नवउदारवाद, जलवायु

संकट, युद्धों और संपूर्ण मानव सभ्यता के विनाश की ओर ले जाने वाली अप्रत्याशित घटनाओं को एकीकृत कर एक-दूसरे से संबद्ध देखने मंच और प्रक्रिया है। यह न्याय, शांति, प्रकृति और हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए गठबंधन है और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने का एक मंच है। इंडिया सोशल फोरम इसी वर्ल्ड सोशल फोरम की गतिविधियों से अपनी प्रेरणा लेता है।

भारत में प्रमुख तिब्बत समर्थक समूह अर्थात् भारत-तिब्बत

मैत्री संघ (आईटीएफएस) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और पटना में इंडिया सोशल फोरम में 'तिब्बत मुक्ति साधना' के पक्ष में अभियान चलाया। इंडिया सोशल फोरम ०२ से ०४ दिसंबर २०२३ तक बिहार विद्यापीठ में आयोजित किया गया। इस विद्यापीठ का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ऐतिहासिक महत्व है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के दौरान स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार का नारा दिया गया। इसके साथ ही बहिष्कार करने वाले छात्रों के लिए विद्यापीठ शिक्षा के माध्यम से एक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। बिहार विद्यापीठ एक ऐसा ही संस्थान था, जहां छात्र भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए शामिल होते थे। इस आयोजन में तिब्बत का स्टाल लगाया गया और प्रतिभागियों के बीच तिब्बत से संबंधित पुस्तकें वितरित की गईं। इस अभियान में भारत-तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा, सलाहकार चंद्र भूषण, राकेश ठाकुर, श्री वी.एन. उपाध्याय, डॉ. ब्रजेश कुमार शर्मा, डॉ. अरुण कुमार शर्मा, श्री प्रभात कुमार, श्री रंजीत कुमार, श्री विनय प्रशांत, श्री प्रशांत गौतम और अन्य सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और प्रतिभागियों को तिब्बत के बारे में समझाया। यह भी बताया गया कि तिब्बत मुक्ति साधना क्या है और तिब्बत की मुक्ति भारत के लिए क्यों मायने रखती है।

फोरम के दौरान ही ०३ दिसंबर २०२३ को भारत-तिब्बत मैत्री संघ द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया। पूर्व संसद सदस्य एवं राजस्थान के लाडनूं स्थित जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. रामजी सिंह ने इस बैठक की शोभा बढ़ाई। आईटीएफएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार ने इस सेमिनार में आए अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत किया।

आईटीएफएस-सीतामढ़ी, बिहार के डॉ. ब्रजेश कुमार शर्मा ने १९५९ में चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डाला। उस समय कम्युनिस्ट चीन द्वारा तिब्बत पर बलपूर्वक कब्जा कर लिए जाने पर लाखों तिब्बतियों की हत्या के बाद परम पावन १४वें दलाई लामा को ८५,००० से अधिक तिब्बतियों साथ भारत में शरण लेनी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, खासकर १९६२, गलवान और अरुणाचल सीमा पर कम्युनिस्ट चीन द्वारा पैदा की गई शत्रुता के बाद। उन्होंने भारतीय सांसदों से संसद भवन में परम पावन दलाई लामा का स्वागत करने और उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न' से सम्मानित करने के लिए अभियान चलाने का अनुरोध किया।

डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि तिब्बत मुक्ति साधना को बड़े पैमाने पर प्रचारित-प्रसारित के लिए भारतीयों को चार प्रमुख जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। पहली, जहां भी संभव हो तिब्बत मुद्दे को उठाएं, दूसरा लगातार मीडिया कर्मियों से जुड़े रहें और तिब्बत के मुद्दों से उन्हें लगातार अवगत कराते रहें, तीसरा अपने से संबंधित सांसदों से अनुरोध करें कि वे भारतीय संसद में तिब्बत के मुद्दों को उठाएं और चौथा हमेशा तिब्बत के शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करते रहें।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूर्व कुलपति मनोज कुमार ने संयुक्त राष्ट्र के तहत वैश्विक संगठनों के कमजोर पड़ने और दुनिया भर में होने वाली त्रासदियों का सर्वमान्य समाधान खोजने में उनकी असमर्थता पर अपनी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, 'चाहे वह यूक्रेन युद्ध का मामला हो या इजरायल-फलस्तीनी संघर्ष का, दुनिया को एकजुट होकर स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान निकालना होगा।' उन्होंने आगे भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बात की, जो चीनी कब्जे के बाद खराब हो गए। इससे भारत को खासकर सीमा संघर्ष और तिब्बत से निकलकर एशिया उपमहाद्वीप में बहने वाली प्रमुख नदियों के जल को चीन द्वारा प्रदूषित करने के कारण भारी नुकसान हुआ है।

वी. एन. उपाध्याय ने तिब्बती मुद्दे के समर्थन में भारत के लिए भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित किया। डॉ. उपाध्याय ने अनुमानित १० लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर जबरन चीनी आवासीय स्कूलों में दाखिला लेने की कुख्यात चीनी नीति पर प्रकाश डाला। यह तिब्बती पहचान को कमजोर करने और तिब्बतियों को बहुसंख्यक चीनी संस्कृति में विलय करने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

डॉ. रामजी सिंह ने निर्दिष्ट किया कि तिब्बत के मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय राजनीतिक दलों को दलीय भावना से ऊपर उठकर एक एकीकृत 'एक भारत, एक दृष्टि' का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता से तिब्बती समुदायों से जुड़ने और भारत-तिब्बत संबंधों को मजबूत करने का अनुरोध किया।

भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय के कार्यवाहक समन्वयक तेनज़िन जॉर्डन ने तिब्बत में कम्युनिस्ट शासन के दौरान तिब्बतियों द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर स्थितियों के बारे में बताया और तिब्बत मुक्ति साधना को लगातार समर्थन देने के लिए भारत सरकार और भारत में तिब्बत समर्थक समूहों के प्रति आभार व्यक्त किया।

श्री सुरेंद्र कुमार भारतीय मित्रों को १४ नवंबर १९६२ को भारत की संसद द्वारा चीन के खिलाफ पारित १९६२ के भारतीय संसद के प्रस्ताव की याद दिलाई। चीन-भारत युद्ध के बाद अपनाए गए इस सर्वसम्मत प्रस्ताव में चीनियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को आखिरी इंच तक वापस पाने का वादा किया गया था।

उन्होंने बताया कि भारत की चीन के प्रति सद्भावना और मित्रता पंचशील सिद्धांत पर आधारित थी। लेकिन चीन ने इस पंचशील नीति के साथ विश्वासघात किया है। पंचशील संधि में एक- दूसरे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति आपसी सम्मान, एक-दूसरे पर आक्रमण न करना, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ उठाना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांत हैं। चीन ने १९६२ में इसका उल्लंघन किया और भारत पर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया।

◆ परम पावन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की ३४वीं वर्षगांठ पर आईटीएफएस का तीसरा महाराष्ट्र सम्मेलन आयोजित

tibet.net, ११ दिसंबर, २०२३

महाराष्ट्र। भारत-तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) का तीसरा महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन १० दिसंबर २०२३ को आईटीएफएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. आनंद कुमार और राज्य अध्यक्ष अमरूद बंसोड़ की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के बदलापुर स्थित श्री बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया।

सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करने वाली गणमान्य हस्तियों में आईटीएफएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. आनंद कुमार, आईटीएफएस के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मनोज कुमार, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा चोयिंग, आईटीएफएस के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष श्री अमरुद बंसोड़, कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज-इंडिया के क्षेत्रीय संयोजक अरविंद निकोसे, भंडारा तिब्बती सेंटलमेंट अधिकारी धोंदुप सांगपो, भारत- तिब्बत समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली की ताशी डेकी शामिल थीं।

प्रोफेसर डॉ. आनंद कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में आईटीएफएस के मूल आदर्श वाक्य यानी 'मुक्त तिब्बत, सुरक्षित भारत' पर बात की और उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से तिब्बत की स्वतंत्रता के संबंधित होने के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में १७ जिला स्तरीय आईटीएफएस इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्य आईटीएफएस अध्यक्ष श्री अमरूद बंसोड़ और उनके सहयोगियों की सराहना की और जिला पदाधिकारियों से तिब्बती हित के लिए और अधिक ताकत और उत्साह के साथ काम करने का आग्रह किया।

सचिव कर्मा चोयिंग ने भारत-तिब्बत संबंधों पर बात करते हुए भारत की तिब्बत नीति और तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने निर्वासित तिब्बती समुदाय को भारत सरकार और लोगों की उदारता के प्रति आभारी बताया। उन्होंने परम पावन दलाई लामा और तिब्बतियों को भाइयों के रूप में स्वागत करने के लिए भारतीयों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने तिब्बत मुक्ति साधना के लिए भारत में तिब्बती समर्थक समूहों के महत्व पर भी प्रकाश डाला और उनसे अधिक भारतीय भाइयों और बहनों तक पहुंचने और उन्हें तिब्बती मुद्दे के बारे में जागरूक समर्थक बनाने के लिए सीटीए का समर्थन जारी रखने की अपील की।

आईटीएफएस का दिनभर चला महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन सभी १७ जिला इकाइयों और उनके सदस्यों द्वारा राज्य स्तर पर तिब्बती मुद्दे और तिब्बत के पक्ष में अभियान के लिए कार्य योजनाओं के समर्थन में एक सर्वसम्मत घोषणा के साथ संपन्न हुआ।

यह सम्मेलन आईटीएफएस के महाराष्ट्र चैप्टर द्वारा परम पावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की ३४वीं वर्षगांठ मनाने के साथ ही अगले ३ वर्षों के लिए महाराष्ट्र में तिब्बती हित के लिए काम करने की कार्य योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत-तिब्बत संबंध, भारत की तिब्बत नीति और तिब्बत की स्वतंत्रता और भारत की सुरक्षा पर भी पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। सम्मेलन और कार्य समिति की बैठक में महाराष्ट्र के १७ जिलों से आईटीएफएस के लगभग १०० सदस्यों ने भाग लिया।

◆ भारत में तिब्बत समर्थक समूह के क्षेत्रीय संयोजक ने गुजरात में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संगोष्ठी आयोजित की

tibet.net, १५ दिसंबर, २०२३

अहमदाबाद। गुजरात साहित्य अकादमी और डॉ. अमित ज्योतिकर फाउंडेशन ने १५ दिसंबर २०२३ को संयुक्त रूप से प्रसिद्ध दलित इतिहासकार और तिब्बत मुक्ति साधना के प्रबल समर्थक डॉ. पी.जी. ज्योतिकर की तीसरी पुण्यतिथि पर 'प्रथम अंतरराष्ट्रीय बौद्ध साहित्य और सांस्कृतिक संगोष्ठी' और पुस्तक विमोचन का आयोजन किया।

सेमिनार की शुरुआत बौद्ध प्रतिनिधियों द्वारा प्रार्थना और स्वर्गीय डॉ. पी.जी. ज्योतिकर के योगदान के बारे में एक लघु वीडियो की प्रस्तुति के साथ हुई। इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कुलदीप अग्निहोत्री, डॉ. हेमंत भट्ट, भिक्षु डॉ. डी. रेवाथा, भिक्षु गेशे तेनज़िन दामचो, डॉ. विजय सुरवड़े और डीजीपी अनिल प्रथम की उपस्थिति में एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

डॉ. अमित ज्योतिकर ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में डॉ. बी.आर. आंबेडकर के बारे में लिखी गई इस पुस्तक का संक्षिप्त परिचय दिया और सेमिनार में भाग लेने वाले गुजरात के सभी क्षेत्रों के सदस्यों और तिब्बती स्वेटर विक्रेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसके अतिरिक्त, गेशे तेनज़िन दामचो ने परम पावन १४वें दलाई लामा का एक सार्वभौमिक संदेश दिया, जिसमें २१वीं सदी का बौद्ध साधक बनने और केवल मंत्र जप के बजाय तर्क पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई गई है। उन्होंने आगे ज्ञान की मदद से विश्वास विकसित करने की आवश्यकता पर बात की और सभा को परम पावन दलाई लामा की चार महान प्रतिबद्धताओं के बारे में बताया, जिनमें से तीन सभी के लिए निहित हैं।

डॉ. पी.जी. ज्योतिकर का १५ दिसंबर २०२० को निधन हो गया था। गुजरात में तिब्बत के समर्थक और तिब्बत मुक्ति साधना के संस्थापक थे और भारत- तिब्बत मैत्री संघ (आईटीएफएस) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। वह एक प्रसिद्ध दलित इतिहासकार, गुजरात में आंबेडकरवादी आंदोलनों के मर्मज्ञ थे। वह आंबेडकरवादी बौद्ध समुदाय में पीजी के नाम से लोकप्रिय थे और बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी अध्यक्ष भी रहे।

◆ तिब्बत को लेकर चीन का नया दुष्प्रचार भारत के लिए चिंता की बात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रशासन ने तिब्बत के विकास को प्रदर्शित करने वाले अपने हालिया 'श्वेत-पत्र' में तिब्बत को 'ज़िज़ांग' नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया है।

indiatoday.in. १२ दिसंबर, २०२३

'ज़िज़ांग'। तिब्बत में खुद को स्थापित करने के चीन ने अपने नवीनतम प्रयास के तहत हाल ही में जारी 'श्वेत-पत्र' में अपनी मंशा को उजागर कर दिया है। इस श्वेत-पत्र का शीर्षक 'नए युग में ज़िज़ांग के शासन पर सीपीसी नीतियां: दृष्टिकोण और उपलब्धियां' है, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के २०१३ में सत्ता संभालने के बाद से तिब्बत में विकास की रूपर

'ज़िज़ांग'। तिब्बत में खुद को स्थापित करने के चीन ने अपने नवीनतम प्रयास के तहत हाल ही में जारी 'श्वेत-पत्र' में अपनी मंशा को उजागर कर दिया है। इस श्वेत-पत्र का शीर्षक 'नए युग में ज़िज़ांग के शासन पर सीपीसी नीतियां: दृष्टिकोण और उपलब्धियां' है, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के २०१३ में सत्ता संभालने के बाद से तिब्बत में विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा गृह युद्ध में विजयी होने के एक साल बाद १९५० में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था। दलाई लामा १९५९ में भारत भाग गए और निर्वासन में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु बने रहे।

भारत में चीन के पर्यवेक्षकों का मानना है कि बीजिंग १९५० से ही तिब्बत पर दुष्प्रचार कर रहा है, जब उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। उनका मानना है कि तिब्बत की जगह ज़िज़ांग नाम का इस्तेमाल करके चीन इस क्षेत्र पर अपना ठप्पा लगा रहा है और तिब्बतियों की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है।

यह सब तिब्बत में चीन की आगामी योजनाओं के अनुरूप चल रहा है। नई दिल्ली स्थित एक पर्यवेक्षक ने कहा, 'भारत के लिए भी इसके गंभीर सुरक्षा निहितार्थ हैं, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को ज़ंगनान कहता है, जो उसके अनुसार ज़िज़ांग का हिस्सा है।' उन्होंने आगे कहा कि चीनी सिविल सोसायटी के कुछ हिस्सों से इसको लेकर स्पष्ट सोच है, जो तिब्बत पर बीजिंग की मनगढ़ंत कहानियों का मुकाबला करने में बेहद मददगार होगी।

अधिकारियों का दावा है कि चीन की स्टेट काउंसिल द्वारा तिब्बत पर १० नवंबर को जारी नवीनतम 'श्वेत-पत्र' आश्चर्यजनक रूप से तिब्बत की स्थिति की एक बेहद आकर्षक छवि प्रस्तुत करता है। यद्यपि शी जिनपिंग प्रशासन के तहत तिब्बत में विकास के आंकड़ों की भरमार है और उपलब्धियों का पुरजोर दावा है, लेकिन 'श्वेत-पत्र' तिब्बत स्टेट पार्टी के दो मुख्य एजेंडे पर बेहद चुप है। ये दो मुख्य एजेंडे हैं- औपनिवेशिक रूप की आवासीय स्कूल प्रणाली और बड़े पैमाने पर श्रमिकों का स्थानांतरण कार्यक्रम। इन दोनों का तिब्बती लोगों और उनकी संस्कृति पर जबरदस्त दुष्प्रभाव पड़ा है।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि तिब्बत पर 'श्वेत-पत्र' १९५० के दशक में तिब्बत को लेकर माओत्से तुंग (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक) के दृष्टिकोण के समान है। १९५१ में झांग जिंगवु और झांग गुओ हुआ की अध्यक्षता वाली सीसीपी तिब्बत कार्य समिति ने रिपोर्ट दी कि 'पूरे देश में समाजवादी परिवर्तन का तेज उभार है' और 'तिब्बत के पड़ोसी अल्पसंख्यक क्षेत्र लोकतांत्रिक सुधार करने की सभी तैयारी कर रहे हैं'। यह उसी तरह का प्रचार था, जैसा कि तिब्बत के विकास पर अब लाए जा रहे कई श्वेत-पत्रों में बताया जा रहा है। इन श्वेत-पत्रों में बताया गया है कि कैसे तिब्बती 'ज़िज़ांग' में समृद्ध हो रहे हैं।

जब यह लगभग तय लगने लगा कि दलाई लामा भारत में शरण मांगेंगे, तो सीसीपी नेतृत्व ने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की। तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन लाई ने १९५६-५७ में भारत की यात्रा की और दलाई लामा से मुलाकात कर उन्हें ल्हासा लौटने के लिए मनाया। उन बैठकों के दौरान माओ की भावना से परम पावन को अवगत कराते हुए चाऊ-एन लाई ने दलाई लामा से वादा किया कि उनकी सलाह के बिना तिब्बत (चामडो क्षेत्र सहित) में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। उन्होंने यह भी वादा किया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी अगले छह वर्षों तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

जैसा कि चीनी विद्वान चेन जियान ने जर्नल ऑफ कोल्ड वॉर स्टडीज के लिए अपने २००६ के लेख में लिखा था, माओ और उनके सहयोगी सीसीपी नेताओं ने विशेष रूप से तिब्बत के राजनीतिक और मठवासी कुलीन वर्ग से निपटने के लिए सैन्य अभियानों के साथ ही सधे हुए कूटनयिक और 'संयुक्त मोर्चा' कार्यों को मिलाकर जारी रखना आवश्यक और जरूरी समझा।

शी जिनपिंग भी माओ की तरह ही राजनीतिक कथानकों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि दुनिया भर के मीडिया संगठनों के साथ ही कुछ चीनी हैंडल सीसीपी द्वारा निर्देशित चीनी प्रचार को हवा दे रहे हैं।

कई निर्वासित तिब्बती शी जिनपिंग पर धार्मिक दमन और तिब्बती संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगाते हैं। इन दमनों का ही नतीजा है कि आत्मदाह की घटनाओं सहित कई तरह से विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे तिब्बत का मुद्दा बीजिंग के लिए बेहद संवेदनशील हो गया। अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि चीनी कथानक की यह नई रणनीति (क्लासिक प्लेबुक) अन्य दक्षिण-एशियाई देशों में कैसे अपना असर दिखा पाती है।

IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tenzin Jorden
Acting Coordinator
India Tibet Coordination Office

आवश्यक सूचना

प्रिय पाठकों,

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

तेनज़िन जॉर्डन
कार्यवाहक समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

कार्यलय पताः भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
फोनः 011–29830578
ई–मेलः coordinator@indiatibet.net

December, 2023, Years: 44 Issue: 12 Regd No. : RNI 34636-79

परम पावन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जाने की ३४वीं वर्षगांठ पर आईटीएफएस का तीसरा महाराष्ट्र सम्मेलन

इंडिया सोशल फोरम में चला तिब्बत जागरुकता अभियान